● वर्ष-6
● अंक-97
रायपुर, गुरुवार
19 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> सौन्दर्य के संसार में खूबसूरत..



हिंदुत्व की पिच पर अखिलेश को घेरने भाजपा की तैयारी

नई दिल्ली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है। राम जन्मभूमि के नाम पर दर्जनों चुनाव लड़ने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के विपरीत हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या के बाद मथुरा या कोई अन्य मंदिर आरएसएस का मुद्दा नहीं रहेगा। इसके बावजूद भाजपा मथुरा को ही मुद्दा बना रही है मंगलवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ-साफ शब्दों में इसकी झलक दे दी है। उन्होंने कहा, अयोध्या हमारी हो गई है, अब मथुरा की बारी है। भाजपा ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दो दिवसीय मंथन सत्र का भी आयोजन मथुरा में ही किया है।

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक

गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए नए नल-जल नियम को मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को रायपुर सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण पेयजल, जनजातीय उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक अधोसंरचना से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गांवों में हर परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए नए नल-जल नियमों को मंजूरी दी। वहीं, नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के कॉलेज के लिए तीन साल में 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी। इनके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का फैसला किया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को



नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके लागू होने पर पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियम निरस्त हो जाएंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अनुदान के लिए पंचायत को मासिक जल प्रभार का कम से कम 50 प्रतिशत संग्रहण करना होगा। वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं, मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए आवंटित की जाएगी।

मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह- मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

विदेश में राहुल ने मोदी सरकार को फिर घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है और युवाओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की समस्या को मीडिया भले ही नजरअंदाज कर दे, लेकिन हकीकत इससे नहीं बदलने वाली। उन्होंने भारत में पिछले करीब एक दशक से जारी अलग-अलग समुदायों के विरोध प्रदर्शनों, लोकतंत्र और वैश्विक आर्थिक बदलावों पर भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने आगाह किया कि अगर अगले पांच या दस साल भी ऐसे ही निकल गए तो देश बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अचानक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ने के साथ अलग-अलग समूह अपने-अपने स्तर पर विरोध करते रहे हैं।



मुख्यमंत्री निवास में दीपावली मिलन समारोह बना आत्मीयता,

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नवा रायपुर स्थित निवास में आज आयोजित दीपावली मिलन समारोह सामाजिक समरसता, आत्मीयता, सेवा भावना और सांस्कृतिक गौरव का अनूठा संगम बना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पद्मश्री सम्मानित विभूतियों, विभिन्न समाजों के वरिष्ठजनों, लोकतंत्र सेनानियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा शिक्षा, सेवा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जागरण, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को विशेष स्वरूप प्रदान किया। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह केवल शुभकामनाओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दशकों से समर्पित भाव से कार्य कर रहे लोगों के सम्मान, उनके अनुभवों को साझा करने और सामाजिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का यादगार अवसर बना।

दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे।

इस बड़े फैसले के तहत केवल नियुक्ति के नियम ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में भी संशोधन किया जाएगा। इसके तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने वाले प्रावधान को बदला जा रहा है। अब यदि किसी शासकीय सेवक



या आवेदक के 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान भी हुई है, तो उसे सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा और न ही उसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी।

क्या था 25 साल पुराना नियम ?

प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह सख्त प्रावधान लागू किया गया था कि तीसरा बच्चा होने पर न तो नया व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकेगा और न ही पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारी को रखा जाएगा; तीसरी संतान होने पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस कड़े कानून के कारण बीते ढाई दशकों में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था या वे पात्रता के बावजूद आवेदन नहीं कर पाए थे।

क्यों पड़ी नियम बदलने की जरूरत ?

जब यह प्रावधान लागू किया गया था, तब देश और राज्य में प्रजनन दर काफी अधिक थी। हालांकि, समय के साथ इसमें बड़ा बदलाव आया है। सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश की कुल सकल प्रजनन दर अब घटकर 2.4 पर आ गई है (जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1.8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 दर्ज की गई है)। वहीं, देश की औसत टीएफआर 1.9 है।

इसके अलावा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य पहले ही इस तरह के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को अपने नियमों में संशोधन कर हटा चुके हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

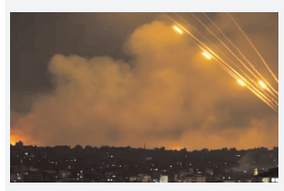
राजनाथ ने जापान के युद्धपोत नाटोरी का लिया जायजा

टोक्यो। चीन जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यामांर और मालदीव से रक्षा समझौते कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत भी ठीक उसी तरह उसके पड़ोसी देशों से डिफेंस समझौते कर रहा है। भारत और चीन के बीच अब तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली रणनीति पर काम चल रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मंगोलियों से रक्षा समझौतों के बाद भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी एडवांस स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण राजनाथ सिंह का टोक्यो दौरा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के साथ 2+2 वार्ता के लिए टोक्यो पहुंचे हैं। 2+2 वार्ता का मतलब एक साथ दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच बैठक होगी। भारत ऐसी बैठकें अमेरिका, रूस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है।



यमन में 60 सैन्य ठिकाने तबाह, 17 लोगों की मौत

रियाद। ईरान समर्थित हूतियों से लड़ रहे सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को बताया कि उसने यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में एक बड़ा हवाई हमला किया है। हूतियों के अनुसार, इस हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने बताया कि मंगलवार को किए गए इन हमलों में राजधानी सना और अमरान, सादा तथा होदेइदा प्रांतों में 60 वैध सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद हूतियों की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को कमजोर करना था। इसके लिए पहाड़ी गोदामों तक जाने वाली उन सुरंगों को नष्ट किया गया जहां बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जाती थीं। इसके साथ ही उन कार्यशालाओं को भी निशाना बनाया गया जहाँ ड्रोन असेंबल किए जाते हैं और रखे जाते हैं। हूती-नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने बताया कि होदेइदा में एक हमले में स्पंज बनाने वाली एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम



भाषण की लंबाई नहीं, थाली और जेब से मापी जाएगी तरक्की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की प्रधानमंत्री के भाषणों की लंबाई से नहीं मापी जाएगी। इसे आम लोगों की थाली में मौजूद खाने और उनकी जेब में बचे पैसों से मापा जाएगा। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार ने 12 साल पहले महंगाई कम करने का वादा किया था। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला। आम लोगों को कम सामान मिल रहा है। उनकी जेब खाली हो रही है। जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मोदी जी ने महंगाई कम करने का वादा किया था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आम आदमी की थाली छोटी होती जा रही है, उसकी जेब खाली होती जा रही है और घर चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आगे सवाल किया, मोदी जी, देश की तरक्की का पैमाना आपके भाषणों की लंबाई नहीं.



वोट चोर नारे पर विवाद कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली। इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इन वीडियो में फिलिबेक कथित तौर पर हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव फिलिबेक ने भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि मामले की सुनवाई के समय संबंधित पीठ के सामने विस्तार से दलीलें रखें। इसके बाद याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी गई। वकील रिजवान अहमद ने बताया कि यह कार्यक्रम तेलंगाना में राज्य सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन समेत कुछ संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया गया था।

रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर रोक की मांग: कारोबार पर असर का दावा

नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शनों को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। व्यापारियों के संगठनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इन प्रदर्शनों से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लिया है। शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस व्यापारियों के संगठनों की उस याचिका पर जारी किए गए हैं, जिसमें प्रदर्शनों का विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 27 नवंबर को प्रदर्शन के पक्ष और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कारोबार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

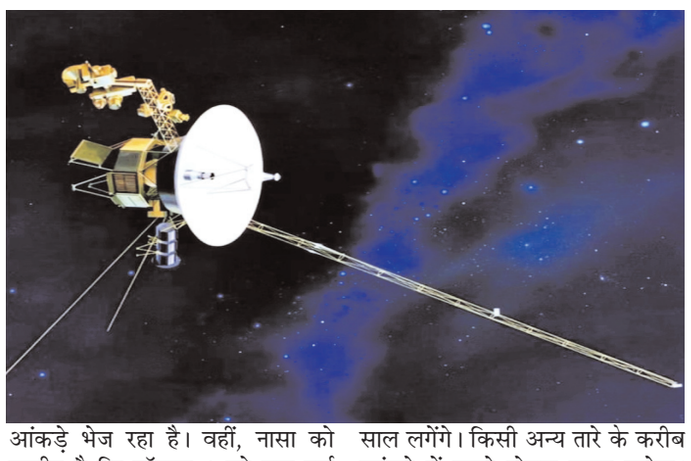
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की अलग-अलग श्रेणियां बनाएगा। कोर्ट ने कहा, इन अलग-अलग श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की तारीखें भी तय करके बताई जाएंगी।

ऐतिहासिकः वॉयजर 1 ने अंतरिक्ष में बनाया नया कीर्तिमान

केप कैनावेरल। नासा के वॉयजर 1 यान ने अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान बनाया है। यह पृथ्वी से एक प्रकाश-दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन चुका है। यह यान लगातार अंतरतारकीय अंतरिक्ष में गहराई तक जा रहा है। करीब 49 साल पहले छोड़ा गया यह अंतरिक्ष यान 26 अरब किलोमीटर से अधिक की अविश्वसनीय दूरी तय कर चुका है। बुधवार को वॉयजर 1 ने महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। अब इसके रेडियो संकेत पृथ्वी तक पहुंचने में ठीक 24 घंटे लेंगे। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए यह एक प्रकाश-दिवस की दूरी है।

क्या है एक प्रकाश-दिवस ?

प्रकाश एक सेकंड में करीब तीन लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 24 घंटे में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उसे एक प्रकाश-दिन कहते हैं। वॉयजर 1 की इस दूरी का मतलब है कि धरती से भेजा गया रेडियो संदेश यान तक पहुंचने में करीब 24 घंटे लेगा। वहीं, उसका जवाब वापस आने में भी 24 घंटे लगेंगे। यानी संदेश भेजने और जवाब पाने में करीब दो दिन लगेंगे। यह यान आज भी अपने पुराने सिस्टम और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पावर जनरेटर की मदद से काम कर रहा है और अंतरिक्ष से वैज्ञानिक



आंकड़े भेज रहा है। वहीं, नासा को उम्मीद है कि वॉयजर 1 को एक पूर्ण प्रकाश-वर्ष तक पहुंचने में 18,000 साल लगेंगे। किसी अन्य तारे के करीब पहुंचने में इससे दोगुना समय लगेगा। परियोजना प्रबंधक सुजैन डोड वॉयजर 1 को पृथ्वी का दूत मानती हैं। डोड ने इसे एक राष्ट्रीय खजाना और वास्तव में असाधारण बताया। वॉयजर यान लगभग हर दिन अपने अज्ञात वातावरण के बारे में जानकारी भेजते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा, आसपास के दबाव, धूल और गांगेय ब्रह्मांडीय किरणें शामिल हैं। डोड के अनुसार, ये यान मौसम उपग्रहों की तरह कार्य करते हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में उड़ान नियंत्रण टीम सप्ताह में एक बार कमांड भेजती है। सितंबर में, नियंत्रकों ने यान के लिए नवीनतम बिजली-बचत प्रयास पूरा किया। अक्तूबर में इससे संपर्क टूट गया था, जिसके कारण का पता लगाया जा रहा है।

ऐतिहासिक उपलब्धियां और गोल्डन रिकॉर्ड

वॉयजर 1 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। यह किसी भी मानव निर्मित वस्तु से अधिक दूर तक यात्रा करने वाला यान है। वर्ष 1990 में वॉयजर 1 ने पृथ्वी की सबसे दूर की तस्वीर ली थी। यह नेपच्यून से परे से ली गई प्रतिष्ठित %पेल ब्लू डॉट% तस्वीर थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री कार्ल सागन ने इस तस्वीर को दुनिया के सामने पेश किया था। प्रत्येक वॉयजर यान में 30 सेंटीमीटर का एक सोने की परत चढ़ा फोनोग्राफिक रिकॉर्ड है। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन, चित्र और आरेख शामिल हैं। डोड ने इसे 1977 से पृथ्वी पर जीवन का एक टाइम कैप्सूल बताया।

वॉयजर मिशन और यात्रा

वॉयजर 1 और इसका जुड़वां वॉयजर 2 लगातार विज्ञान और इंजीनियरिंग डेटा भेज रहे हैं। ये 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में अलग-अलग बिंदुओं की ओर बढ़ रहे हैं। वॉयजर 2 को 1977 में वॉयजर 1 से दो सप्ताह पहले प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि, वॉयजर 2 वर्ष 2035 तक एक प्रकाश-दिवस का निशान हासिल नहीं कर पाएगा। वॉयजर 1 ने 1979 और 1980 में बृहस्पति और शनि के पास से उड़ान भरी।

एमसीबी के कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में खामियां, किसान कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप

एमसीबी। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कई खामियों को उजागर करने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सरगुजा संभाग प्रभारी बिमलेश तिवारी ने भरतपुर विकासखंड के बहारसी और कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, हमालों की मजदूरी भुगतान व्यवस्था और किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुंवारपुर केंद्र में निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। बिमलेश तिवारी ने बताया कि वे किसान कांग्रेस की बैठक के सिलसिले में भरतपुर विकासखंड पहुंचे थे, इसी दौरान धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों और हमालों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में हमालों को शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति बोरी के हिसाब से मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें दैनिक मजदूरी दर से भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमालों को निर्धारित नियमों के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए।



कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किए। यहां हमालों ने बताया कि दैनिक रोजी के हिसाब से मजदूरी दिया जाता है जबकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें प्रति बोरी खाली करने का निर्धारित दर के अनुसार देना चाहिए। समिति प्रबंधक भी मौके पर मौजूद नहीं है। किसानों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं है। 40 किलो भर्ती लेना चाहिए लेकिन किसानों से 40 किलो 800 ग्राम लिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक की अनुपस्थिति का मुद्दा भी सामने आया। तिवारी ने कहा कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान समिति प्रबंधक की मौजूदगी जरूरी है, ताकि किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। किसान कांग्रेस नेता ने खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि धान बेचने के लिए दूर-दराज से किसान खरीदी केंद्र पहुंचते हैं।

2398 किसानों से 8205 मीट्रिक टन धान खरीदा



धमतरी। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं। मंगलवार को जिले के अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में व्यापारियों और राइस मिल के स्टॉक में अनियमितता सामने आई। चार स्थानों पर जांच के दौरान कुल 1,085 कट्टा से अधिक धान जब्ती की कार्रवाई की गई है। वहीं, धान खरीदी केंद्रों में भी खरीदी का सिलसिला जारी है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ग्राम बिरझूली में छोटे व्यापारी राजेंद्र साहू के पास निर्धारित सीमा से अधिक धान मिलने पर 80 कट्टा धान जब्त किया गया।

ड्राइवर महासंगठन का जश्न, आंदोलन के बीच एक मांग पूरी होते ही खुशी से झूम उठे ड्राइवर

संघर्ष और बातचीत के बाद ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग पर सहमति बनने पर धमतरी में निकाली भव्य बाइक रैली





धमतरी। ड्राइवर महासंगठन के आंदोलन के बाद तीन मांगों में से एक मांग पर सरकार की सहमति मिल गई है। इसकी जानकारी मिलते ही ड्राइवर संगठन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी खुशी का इजहार करने मंगलवार को धमतरी में ड्राइवर महासंगठन ने भव्य बाइक रैली निकाली।

डीजे की धुन, नाचते-गाते सदस्य और एक-दूसरे को बधाई देते ड्राइवरों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई किलोमीटर तक निकली इस रैली में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए। हालांकि, संगठन ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाकी दो मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय में मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

दरअसल, ड्राइवर महासंगठन अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन कर रहा था। धमतरी जिले के भी चिटौद में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी था जहां धमतरी और बालोद जिले के ड्राइवरों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की थी। आंदोलन के दौरान बसों और मालवाहक वाहनों को रोककर चालकों से समर्थन देने की अपील भी की गई।

लगातार कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बीच प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी रहा। ड्राइवर महासंगठन की प्रमुख मांगों में ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग का गठन शामिल था। लंबे संघर्ष और बातचीत के बाद ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग पर सरकार ने सहमति जताई है। इसे संगठन अपनी पहली बड़ी जीत मान रहा है।

इसी उपलब्धि की खुशी में पुरूर से बाइक रैली निकाली गई, जो धमतरी शहर पहुंची। रैली अंबेडकर चौक, छत्रपति शिवाजी चौक, घड़ी चौक, सिहावा चौक और पावर हाउस होते हुए अर्जुनी चौक पहुंची। इसके बाद वापस पुरूर पहुंचकर रैली का समापन किया गया। इस दौरान डीजे की धुन पर ड्राइवर महासंगठन के सदस्य जमकर थिरकते नजर आए। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई।

साइबर ठगी के लिए म्युल बैंक खाते से 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन, पखांजूर के 2 आरोपी गिरफ्तार

कांकेर। म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले दो आरोपियों को कांकेर पुलिस ने पखांजूर से गिरफ्तार किया है। आरोपी इन बैंक खाते के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की रकम का लेन-देन कर रहे थे। जांच में इस बैंक खाते के खिलाफ विभिन्न राज्यों से कुल 12 साइबर शिकायतें दर्ज होने का खुलासा हुआ है। वहीं, खाते के जरिए करीब 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार 435 रुपये की ठगी से संबंधित रकम का लेन-देन सामने आया है।

पखांजूर एडिशनल एसपी राकेश कुर्रे के अनुसार पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों की जांच की जा रही है। इसी दौरान थाना पखांजूर क्षेत्र के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के एक खाते की जांच में साइबर ठगी



की रकम के लेन-देन का मामला सामने आया। धोखाधड़ी का पैसा म्यूल बैंक खातों में करते थे जमा जांच में बैंक खाता धारक सिराज बैरागी (25 वर्ष), निवासी पीव्ही-42 विद्यानगर की संलिप्तता पाए जाने पर थाना पखांजूर में धारा 318(2), 318(4) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान सिराज ने अपने साथी सूरज दास (25 वर्ष), निवासी पीव्ही-13 श्यामनगर के साथ मिलकर पीड़ितों से धोखाधड़ी कर प्राप्त रकम का बैंक खाते के माध्यम से लेन-देन करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की पासबुक, एक पैन कार्ड और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों के बैंकिंग लेन-देन और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुर्रे, एसडीओपी कुलदीप बंजारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेज कुमार वर्मा सहित थाना पखांजूर पुलिस और साइबर सेल कांकेर की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कांकेर पुलिस की आम लोगों से अपील, किसी को ना दें अपना बैंक खाता

कांकेर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कमीशन या लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी से साझा न करें।

परामर्श केंद्र की काउंसलर को हटाया

जांजगीर-चांपा। जिले के महिला थाना में संचालित परिवार परामर्श केंद्र की एक और काउंसलर की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक ने रद्द कर दी है। बीजेपी नेत्री और परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे को एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने पद से हटा दिया है। उनके खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लेने और काम नहीं दिलाने की शिकायत सामने आई है।मिली जानकारी के अनुसार, कोरबा निवासी पारस जैन ने आरोप लगाया है कि संतोषी दुबे ने एनजीओ के माध्यम से पांच अलग-अलग स्थानों पर काम दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बदले संतोषी दुबे को डेढ़ लाख रुपये और उनके एक सहयोगी को साढ़े तीन लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए गए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो संबंधित लोगों को काम दिलाया गया और न ही पैसे वापस किए गए। काफी समय तक समाधान नहीं मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने जांजगीर-चांपा एसपी से शिकायत की। मामला सामने आने के बाद एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने संतोषी दुबे को परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर पद से हटा दिया है। मामले की जांच परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी और अजाक थाना के डीएसपी को सौंपी है। पुलिस अधिकारियों को शिकायत से जुड़े आरोपों और लेन-देन की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह के भीतर परिवार परामर्श केंद्र की दूसरी महिला काउंसलर की नियुक्ति रद्द की गई है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य और काउंसलर पूजा राठौर की नियुक्ति भी निरस्त की थी।



सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, नक्सलियों का डंप बरामद, 50 बीजीएल सेल जब्त



बीजापुर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। उसूर थाना क्षेत्र के पुजारीकांकेर जंगल में सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। इसमें 50 नग बीजीएल सेल मिले हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, खुफिया आसूचना के आधार पर थाना उसूर, आवापल्ली, पामेड़ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 196वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। अभियान के दौरान जवानों ने पुजारीकांकेर के जंगल में कुछ संदिग्ध स्थानों की पहचान की।सघन तलाशी लेने पर नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए डंप से 50 नग बीजीएल सेल बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में थाना उसूर में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान और सर्चिंग जारी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कबीरधाम बिजली कंपनी के दो केंद्रों में 4.30 करोड़ का गबन

कवर्धा। कबीरधाम जिले में सरकारी राशि के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दो विद्युत वितरण केंद्रों में पदस्थ रहे एक कर्मचारी पर 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये के वित्तीय गबन का आरोप है। मामले में पिपरिया पुलिस ने आरोपी कर्मचारी मनोज साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच कंपनी की राशि बैंक खाते में जमा नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, मामले की शिकायत सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने थाना पिपरिया में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि विद्युत वितरण केंद्र रवेली में सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदस्थ मनोज साहू ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की 3 करोड़ 17 लाख 90 हजार 699 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की। इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 127/2026 के तहत धोखाधड़ी, कूटरचना और गबन सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

बस्तर बनेगा आदर्श जनजातीय क्षेत्रः बुनियादी ढांचे

जगदलपुर। बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए प्रस्तावित कुल 187.43 करोड़ रुपए की कार्ययोजना में से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95% जनजातीय आबादी (20.69 लाख से अधिक) के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सहेजना है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और वन अधिकारों के सशक्तिकरण की दिशा में बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोडऩे के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (पहले चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई।

महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण किया प्रसाद

बलरामपुर। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में भी यह त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने मां महामाया मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आंवला पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। रामानुजगंज में कन्हर नदी तट पर मां महामाया मंदिर में कई महिलाएं जुटी थीं। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी की पूजा को समर्पित है। इस मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है, आंवला वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने और ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु महिला नागवंती पांडेय ने कहा कि आज अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की फेरी लगाते हुए परिक्रमा करते हैं। पूजा अर्चना करते हैं, मीठा भोजन बनाकर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर खाते हैं।

दुर्ग की बंद फैक्ट्री में भीषण आग दमकल कर्मियों ने संभाला मोर्चा

दुर्ग। स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस आग में फैक्ट्री का पुराना सामान जलकर राख हो गया है। लोन जमा नहीं करने की वजह से फैक्ट्री को दो साल पहले सीज कर दिया गया था। इस फैक्ट्री में डिटर्जेंट पाउडर और अगरबत्ती बनाने का काम होता था। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दुर्ग भिलाई पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आग पूरे फैक्ट्री परिसर में फैल चुकी है। यह घटना जामुल थाना क्षेत्र के राजीव नगर इंडस्ट्रियल एरिया की है। यहां गणपति फैक्ट्री में आग लगी। देखते देखते इस आग ने भयंकर रूप ले लिया। आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम आग बुझाने का काम कर रही है। आग बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है। आग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

जुआ खेल रहे लोगों पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस

मुंगेली। एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर दीपावली के दौरान जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिले में 'ऑपरेशन बाज' चलाया जा रहा। इसी अभियान के तहत 7 नवंबर की रात करीब 8ः53 बजे फास्टरपुर-सेतगंगा थाने की पुलिस को ग्राम शुक्लाभाठा में जुआ खेले जाने की सूचना मिली। पुलिस टीम गवाहों और स्टाफ के साथ सरकारी वाहन से मौके पर पहुंची। वहां कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए जुआरियों को छुड़ाने के लिए गांव के कुछ लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को गालियां दीं, धमकाया और हाथ-मुक्कों व थप्पड़ों से मारपीट की। आरोपियों ने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालते हुए जुआ फड़ से जब्त सामान और रकम के साथ पुलिसकर्मियों के पास मौजूद रुपए भी लूट लिए। इस मामले में कुल 4,470 रुपए लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

एनएसयुआई ने शुरू की संगठन विस्तार की तैयारी, छात्रों की गूंज

बलौदाबाजार। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने संगठन विस्तार की तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ह्स्ढ्ढ के 'छात्रों की गूंज ङ्क छात्र सदस्यता अभियान' के पोस्टर का विमोचन किया गया। संगठन ने इस अभियान के जरिए जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने और महाविद्यालयों में अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बनाई है। 17 नवंबर 2026 को जिला अध्यक्ष विवेक यदु के नेतृत्व में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों और संगठन की अलग-अलग इकाइयों से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में अब तक की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी



कार्ययोजना तैयार की गई। खास तौर पर महाविद्यालयों में छात्र संगठनों की सक्रियता, विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक का प्रमुख आकर्षण 'छात्रों की गूंज ङ्क छात्र सदस्यता अभियान' के पोस्टर का विमोचन रहा। संगठन इस अभियान के माध्यम से जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को सदस्यता दिलाने और उनकी समस्याओं को संगठन के मंच तक लाने की तैयारी कर रहा है। अभियान का संदेश 'हर छात्र की आवाज ङ्क ह्स्ढ्ढ के साथ!' रखा गया है। इसके तहत बेहतर शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षित कॉलेज परिसर, छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं और युवा नेतृत्व के निर्माण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। संगठन की योजना है कि केवल सदस्यता बढ़ाने तक अभियान सीमित न रहे, बल्कि कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उन्हें संबंधित कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन के सामने उठाया जाए। जिला अध्यक्ष विवेक यदु ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' सदस्यता अभियान के माध्यम से जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास केवल सदस्य संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की समस्याओं और अधिकारों को मजबूती से उठाना है। छात्रवृत्ति, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षित कैंपस और महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए नए छात्र नेतृत्व को आगे लाया जाएगा। जिले के अलग-अलग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया जाए। संगठन का मानना है कि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कई बार अपनी समस्याएं रखने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता। प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति, फीस, दस्तावेजों से जुड़ी दिक्कतें, कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी और सुरक्षित कैंपस जैसे विषय विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकते हैं।

लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की दबिश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आईटी की टीम ने लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के अलग-अलग जगहों पर आईटी की टीम पहुंची।

आयकर विभाग की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी तीन गाड़ियों में विद्या नगर स्थित कारोबारी के निवास प्रकाश कुंज पहुंचे।

इसके साथ ही व्यापार विहार स्थित मित्तल स्टील इस्पात और स्टीलमार्ट के कार्यालय एवं दुकान में भी टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि यहां



हनुमान हार्डवेयर स्टोर के नाम से भी कारोबार संचालित होता है। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी प्रतिष्ठानों और निवास से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। वहीं कारोबारी जयप्रकाश मित्तल से भी पूछताछ की जा रही है।फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।हालांकि इस छापेमारी के पीछे की वजह और जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आईटी की टीम ने रायपुर,रायगढ़, जांजगीर चांपा और अंबिकापुर में भी दबिश दी है। रायपुर में क्क्क ग्रुप के मालिक रमेशचन्द्र अग्रवाल के ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। इस छापेमारी में विभाग की एक दर्जन से अधिक टीमें शामिल बताई जा रही हैं। रमेशचन्द्र अग्रवाल सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदार माने जाते हैं

संक्षिप्त समाचार

रायपुर में 6 दिसंबर को होगा साहू युवक-युवती परिचय सम्मेलन

रायपुर। राजधानी रायपुर में साहू समाज का



भव्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन आगामी 6 दिसंबर 2026 को संतोषी नगर स्थित मां कर्मा धाम में आयोजित किया जाएगा। शहर जिला साहू संघ, रायपुर के तत्वावधान में होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेशभर से विवाह योग्य युवक-युवतियां शामिल होकर मंच से अपना परिचय देंगे और अपने लिए सुयोग्य जीवनसाथी की तलाश करेंगे। सम्मेलन में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन को लेकर शहर जिला साहू संघ ने पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी है। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन सामाजिक बंधुओं के आग्रह पर इसे पांच दिन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप साहू ने प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू सहित प्रदेश साहू संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान पदाधिकारी अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

भारतीय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी की घोषित

रायपुर। भारतीय शिक्षा बोर्ड (केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) एवं हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी घोषित कर दी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10वीं) का आयोजन 8 मार्च 2027 से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2027 तक किया जाएगा। वहीं, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल परीक्षा (कक्षा 12वीं) 8 मार्च 2027 से शुरू होकर 30 मार्च 2027 तक आयोजित होगी। बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में शामिल है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में भारतीय शिक्षा बोर्ड से 3 हाईस्कूल, 3 हायर सेकेंडरी स्कूल तथा 10 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय संबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की व्यवस्था के तहत बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इससे संबंधित विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना होगा और वे अपने संबद्ध विद्यालयों में ही परीक्षा दे सकेंगे।

10 लाख के माल के साथ गुढियारी थाने का हिस्ट्रीशीटर रोहन गिरफ्तार

रायपुर। परिवार की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, नगदी समेत अन्य सामान की चोरी करने वाले गुढियारी थाने के हिस्ट्रीशीटर रोहन ताम्रकार को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद किया गया है। मामला खमतराई थाना क्षेत्र के शिवानंद नगर स्थित अंजनी विहार कॉलोनी का है। प्रार्थी शिव निर्मलकर 8 नवंबर 2026 को अपने मकान में ताला लगाकर परिवार के साथ गृहग्राम गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने सूने मकान को निशाना बना लिया। 12 नवंबर को जब परिवार वापस लौटा तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखने पर अलमारी खुली थी और उसका लॉकर भी टूटा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान गायब थे। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा खमतराई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए।

आरोपी के भागने पर पुलिस इंस्पेक्टर विनीत दुबे निलंबित

रायपुर। रायपुर पुलिस अमले में एक बड़ी विभागीय कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। रायपुर में 25 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी मांगने के मामले में यह एक्शन लिया गया है। पुलिस की गोपनीय रणनीति लीक होने पर इंस्पेक्टर विनीत दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कदम से विभाग के भीतर सूचना तंत्र पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिये है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध से जुड़ा मामला है। अपराध क्रमांक 403/ 2026 के तहत तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने शोएब ढेबर को पकड़ने के लिए कई जगहों पर रेड की कार्रवाई की। लेकिन रेड की कार्रवाई के पहले ही आरोपी को पुलिस की गतिविधि की भनक लग गई। खमारडीह इलाके में पुलिस ने पहुंचने के पहले ही आरोपी वहां से निकल गया। इसके बाद विभाग के अंदर से ही सूचना लीक होने की आशंका जताई गई। यह सूचना लीक होने के बाद गोपनीय स्तर पर जांच शुरू की गई।

विकसित भारत-2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम : राज्यपाल

वंदे मातरम् राज्य युवा शिविर में राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए युवाओं से किया संवाद

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि भारत युवाओं का देश है, जहाँ देश की लगभग 35 प्रतिशत आबादी युवा है। यही युवा शक्ति देश को वर्ष 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। युवाओं की शिक्षा, कौशल, कड़ी मेहनत और नवाचार से ही देश की प्रगति की दिशा तय होगी। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे जीवन में जो भी कार्य करें, उसे पूरी लगन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें ताकि समाज और राष्ट्र का भला हो।

राज्यपाल डेका आज रायपुर के लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित वंदे मातरम् राज्य युवा शिविर में विभिन्न राज्यों से आए युवा स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। 17 से 23 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस सात दिवसीय शिविर में महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के युवा प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि ऐसे युवा शिविर अलग-अलग राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और विचारों को जानने-समझने का बेहतरीन अवसर देते हैं। इससे आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और नेतृत्व क्षमताओं का विकास होता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया।

युवाओं को सफलता के सूत्र बताते हुए राज्यपाल ने धैर्य, दृढ़ता और स्पष्ट उद्देश्य को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास, कठोर परिश्रम और अनुशासन जरूरी है। उन्होंने कहा कि टालमटोल से बचें युवाओं को आज का काम



कल पर टालने की आदत से बचना चाहिए। श्री डेका ने कहा कि समय की पाबंदी ही सफलता की असली नींव है।

राज्यपाल ने युवाओं को गांवों की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि गांवों में विकास और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। युवाओं को गांवों की जरूरतें समझकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तलाशने चाहिए। उन्होंने कृषि को पारंपरिक पेशे से आगे बढ़ाकर उद्यमिता और स्टार्टअप का माध्यम बनाने पर जोर दिया। युवाओं से जैविक खेती, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की गई।

बस्तर का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि जहाँ सुरक्षा होती है, वहीं शांति और विकास का माहौल बनता है। नक्सलवाद का प्रभाव कम होने और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने से बस्तर में शांति स्थापित हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जिन इलाकों में कभी संचार साधनों का अभाव था, वहाँ अब मोबाइल टावर, रेडियो, और टेलीविजन की पहुँच बढ़ रही है तथा बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली युवा स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं के सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें सफल जीवन के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक श्री अर्पित तिवारी ने शिविर के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना सहित लोकभवन के अधिकारी और विभिन्न राज्यों के अधिकारी एवं युवा प्रतिभागी उपस्थित रहे।

दिवंगत आरक्षक के पुत्र को बाल आरक्षक के रूप में दी जा चुकी है अनुकंपा नियुक्ति

दिवंगत आरक्षक के परिवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सौंपा बीमा राशि का चेक

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह एवं जेल मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज महानदी भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम में पदस्थ रहे दिवंगत आरक्षक स्वर्गीय श्री सोनवीर कुमार की पत्नी श्रीमती प्रीति देवी को बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दिवंगत आरक्षक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोने की क्षति अपूरणीय होती है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था परिवार को आगे बढ़ने का संबल प्रदान करती है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पुलिसकर्मी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिसकर्मियों के वेतन खातों से जुड़ी बीमा सुविधाएं आकस्मिक परिस्थितियों



में उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमा सुरक्षा व्यवस्था का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। विगत दिनों नगर सैनिकों एवं फायर फाइटर्स को भी सैलरी पैकेज बीमा योजना से जोड़ा गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले इन जवानों और उनके परिवारों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सके।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से कहा कि बीमा राशि प्राप्त करने वाले परिवार को इसके सुरक्षित निवेश एवं समुचित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए, ताकि यह राशि परिवार की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिवंगत आरक्षक के परिवार को शासन की ओर से देय शेष सहायता एवं अन्य सुविधाएं भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्री सोनवीर कुमार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम के अंतर्गत कैंप घाघरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने पुलिस बल में 12 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी थीं। विगत 22 दिसम्बर 2025 को गोली लगने की घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के सैलरी पैकेज के अंतर्गत उनकी पत्नी एवं नामिनी श्रीमती प्रीति देवी को 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उनके पुत्र श्री दिवेश कुमार को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जा चुकी है।

आयकर विभाग ने रायपुर-बिलासपुर समेत 5 जिलों में एक साथ छापेमारी की

बर्बरीक कंपनी समेत कई कारोबारियों के रिकॉर्ड खंगाल रही टीम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बुधवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के पांच जिलों में एक साथ छापेमारी की है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा में आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कर चोरी की सूचना के आधार पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह आयकर विभाग ने कई जगहों पर एक साथ दबिश दी। रायपुर में पीआरए ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई। खम्हारडीह स्थित बनियान ट्री सोसाइटी में कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल और महेश राय अग्रवाल के घरों पर टीम जांच कर रही है। बिलासपुर में जेपी मित्तल और रायगढ़ में बर्बरीक ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक,



आयकर विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए 16 अलग-अलग टीमें गठित की थीं। इन टीमों ने बुधवार सुबह एक साथ अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर जांच शुरू की। अचानक हुई इस कार्रवाई से संबंधित कारोबारियों और प्रतिष्ठानों में हलचल मच गई। कार्रवाई में रायपुर और रायगढ़ स्थित बर्बरीक कंपनी के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमों के पहुंचने की जानकारी सामने आई है। रायपुर में रिंग रोड, शंकर नगर और खम्हारडीह क्षेत्र में भी छापेमारी की सूचना है। विभाग की टीमें संबंधित दस्तावेजों, कारोबारी लेनदेन और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की इस कार्रवाई का दायरा कई जिलों तक फैला हुआ है। टीमों की ओर से संबंधित कारोबारियों के व्यावसायिक रिकॉर्ड, आय-व्यय के ब्योरे और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार्रवाई में कितनी संपत्ति, नकदी या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। विभाग की ओर से देर शाम अधिकृत जानकारी दिए जाने की संभावना है।

10 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग-स्टाफ का अनिश्चितकालीन आंदोलन

■ ग्रेड-पे और नियमितीकरण की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग के 10 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन आंदोलन बुधवार से शुरू हो गया है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले नियमित, संविदा और डेली वेजेस पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

आंदोलन रोज सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगा। संघ की प्रमुख मांग साल 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, संविदा, डेली वेजेस और एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने के साथ नर्सिंग संवर्ग के लिए ग्रेड-पे का आदेश जारी करने की है।

संघ पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को आंदोलन की सूचना दी थी। विभाग की ओर से बताया गया कि 2018 की कमेटी की अनुशंसाओं पर काम चल रहा है।

हालांकि, संघ ने इस जवाब को संतोषजनक नहीं माना और आंदोलन शुरू



कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत के मुताबिक, लंबे समय से मांगों को लेकर शासन के सामने बात रखी जा रही है, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं हुए हैं।

नर्सिंग संवर्ग की वेतन संबंधी मांग नई नहीं है। साल 2018 में गठित कमेटी ने स्टाफ नर्सों का ग्रेड-पे 2800 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा 1200 रुपए ड्रेस अलाउंस और 4800 रुपए नर्सिंग अलाउंस देने का सुझाव दिया गया था।एसोसिएशन का कहना है कि कमेटी की सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हुआ है। संघ अलग-अलग नर्सिंग पदों के लिए ग्रेड-पे में बढ़ोतरी और लंबित वेतन संबंधी आदेश जारी करने की मांग भी कर रहा है।

पटवारियों की हड़ताल बेअसर, निर्बाध जारी है धान खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के बावजूद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम निर्बाध रूप से जारी है। शासन का कहना है कि चाक-चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था के चलते किसानों को अपना धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही राज्य के किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है।

गौरतलब है कि राज्य में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। शासन का मानना है कि पटवारियों ने धान खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दे को आधार बनाकर अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। पटवारियों की हड़ताल का धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ा है।

राज्य सरकार ने मार्कफेड, सहकारिता सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को धान उपार्जन व्यवस्था से जोड़कर पूरे प्रदेश में धान खरीदी का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया है। जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अमले की भी सेवाएं ली जा रही हैं।

राज्य सरकार ने सभी धान उपार्जन केंद्रों



में किसानों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। टोकन जारी करने से लेकर धान की तौलाई, बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, पेयजल और किसानों के बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान खरीदी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल में विधिवत पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा 21 क्विंटल से कम धान भी समर्थन मूल्य पर बेचता है, तो उसकी आदान सहायता राशि में कोई कटौती नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से विशेषकर कम उपज वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा के किसान भोज कुमार पटेल सरकार के इस फैसले से खुश हैं। 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार का कहना है कि यदि कोई किसान किसी कारणवश प्रति एकड़ 15 या 16 क्विंटल ही धान बेच पाता है, तो भी उसे पूरी आदान सहायता मिलने से आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री साय का आभार जताया है। भोज कुमार ने गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। उनका कहना है कि इस बार आदान सहायता की राशि से वह ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धान खरीदी का विशेष महत्व है। लाखों किसान परिवारों की आर्थिक खुशहाली इससे जुड़ी हुई है। यही वजह है कि राज्य सरकार धान खरीदी व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि वह पटवारियों की अनुचित मांगों के दबाव में आए बिना पूरे प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था का बेहतर संचालन सुनिश्चित करेगी। किसी भी स्थिति में किसानों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी।

दीपक टंडन ठगी मामला : पति-पत्नी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी पुलिस

■ जानिए कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था आरोपी

रायपुर। करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में आरोपी दीपक टंडन से रायपुर पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पूछताछ में जुटे हुए हैं। दीपक टंडन के बाद अब उसकी पत्नी बरखा टंडन से भी पुलिस हिरासत में पूछताछ की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में रिमांड आवेदन लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस दीपक और बरखा टंडन को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, ताकि ठगी के पूरे नेटवर्क, लेनदेन और अन्य सहयोगियों की भूमिका का पता लगाया जा सके। पूछताछ में दो डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और टीआई स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

दीपक टंडन ठगी की वारदाते सुनियोजित तरीके से करता था। अब तक सामने आए मामलों में एक तरीका समान दिखाई देता है। वह पहले खुद को प्रभावशाली नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के करीब बताता था। इसके बाद सरकारी विभागों में काम कराने, कोयला खदानों में ठेका दिलाने, जमीन और होटल के कारोबार में फायदा दिलाने जैसे प्रस्ताव देकर लोगों का विश्वास जीतता था। लोगों को भरोसे में लेने के बाद वह लाखों रुपये लेता था। जब काम नहीं होता और लोग पैसे वापस मांगते थे तो उन्हें टालने या धमकाने के आरोप भी सामने आए हैं।

जांच के दौरान पुलिस ने दीपक टंडन के घर, होटल और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। कार्रवाई में दीपक और बरखा के मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीडी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए



हैं। इनकी जांच के जरिए पुलिस वित्तीय लेनदेन और ठगी से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस का मुख्य फोकस इस बात पर है कि ठगी से हासिल करोड़ों रुपये कहां खपाए गए और किन-किन लोगों तक रकम पहुंची। इसके अलावा दीपक के संपर्क में रहने वाले लोगों की भूमिका, फर्जी दस्तावेजों, बैंक खातों और संभावित बेनामी संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दीपक टंडन ने ठगी के नेटवर्क से जुड़े कुछ सहयोगियों के नाम बताए हैं। पुलिस अब इन लोगों की भूमिका और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। दीपक को 19 नवंबर को कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा।

इस मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोप है कि अच्छी पोस्टिंग दिलाने का झांसा देकर दीपक टंडन ने चार एडिशनल एसपी, तीन डीएसपी और टीआई समेत कई पुलिस अधिकारियों से रकम ली थी। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ अधिकारियों ने मनचाही पोस्टिंग पाने के लिए दीपक को पैसे दिए थे। हालांकि, उनका काम नहीं हुआ। इसके बाद जब अधिकारियों ने रकम वापस मांगी तो दीपक टालमटोल करता रहा।

दावा किया जा रहा है कि एक एएसपी ने दबाव बनाकर अपनी रकम वापस ले ली, जबकि तीन अन्य अधिकारियों की रकम फंस गई। यह भी आरोप है कि बाद में रकम की वसूली के लिए कुछ अधिकारी उसका होटल चलाने लगे थे। हालांकि, पुलिस अधिकारियों से पैसे लेने और होटल संचालन से जुड़े इन दावों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पूछताछ और जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच से ठगी के नेटवर्क, रकम के लेनदेन और इसमें शामिल अन्य लोगों को लेकर अहम जानकारी सामने आ सकती है।

बिलॉन्गिंग के खुलासे पर मेनका गांधी की चुप्पी

हरीश गुप्ता

मेनका गांधी ने सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉनिंगं : ए जर्नी ऑफ लव' पर अब तक चुप्पी साध रखी है, जिसमें 'छोटी बहू' पर एक अध्याय शामिल है। ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें अपने और अपने दिवंगत पति संजय गांधी के बारे में फैलाई गई झूठी बातों के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, जिसे उनका खेमा झूठ मानता है। खबरों के मुताबिक, यह सलाह न सिर्फ परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मिली है। खास तौर पर भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मेनका और सोनिया गांधी के बीच टकराव प्राइम टाइम टेलीविजन पर एक धमाकेदार तमाशा बन सकता है। आखिर, गांधी परिवार के झगड़ों जैसा राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व शायद ही किसी और पारिवारिक झगड़े में हो। लेकिन मेनका गांधी फिलहाल इस विवाद में कूदने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं दिखतीं। वह और उनके बेटे वरुण गांधी दोनों भाजपा में हैं, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने दोनों में से किसी को भी टिकट नहीं दिया था। मेनका का खेमा सोनिया के विवरण को एकतरफा मानता है, लेकिन मेनका ने अभी तक जवाबी हमला करने के प्रलोभन से खुद को दूर रखा है। हालांकि, वह बाद में अपनी चुप्पी तोड़ सकती हैं और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकती हैं। इसका एक उदाहरण पहले से मौजूद है। इससे पहले, मेनका ने ब्रिटेन में लेखिका कैथरीन फ्रैंक के खिलाफ इंदिरा गांधी की जीवनी में संजय गांधी से संबंधित अंशों को लेकर अदालत के बाहर मानहानि का समझौता किया था। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी ने मेनका गांधी के बारे में जो कुछ भी लिखा है, वह वर्षों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। 2003 में स्टार वर्ल्ड पर सिमी गरेवाल के साथ उनका एक साक्षात्कार 23 साल बाद फिर से सामने आया है। मेनका ने 17 साल की उम्र में संजय से मिलने, इंदिरा, राजीव और सोनिया के साथ एक ही छत के नीचे रहने और उन तनावों के बारे में विस्तार से बात की, जिनके कारण अंततः उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने आपातकाल के दौरान संजय का बचाव करते हुए तर्क दिया कि नसबंदी कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। यह 2003 में मेनका का बयान था। अब सोनिया गांधी ने 23 साल बाद अपना पक्ष प्रकाशित किया है। फिलहाल मेनका का इरादा इस विवाद में एक बार फिर उलझने के बजाय सोनिया की किताब को खुद बोलने देने का ही नजर आता है। यानी अभी कोई नई 'तू-तू मैं-मैं' नहीं। मेनका गांधी ने भले ही इस विवाद में पड़ने से परहेज किया हो, लेकिन गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भाजपा के लिए एक तरह से मददगार साबित होते दिखे। पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना 'गुजराती मित्र' बताते हुए कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं। पित्रोदा ने यह कदम तब उठाया जब सोनिया गांधी ने अपनी किताब में मोदी और उनकी नीतियों पर तीखा हमला किया और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा था। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद पित्रोदा इसी महीने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हो रही राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के मुख्य आयोजक बने हुए हैं। पित्रोदा और मोदी के बीच साझा 'गुजराती कनेक्शन' कौन है? बताया जाता है कि वह व्यक्ति दिनेश त्रिवेदी हैं, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि त्रिवेदी मोदी के काफी करीबी रहे हैं और उन्होंने ही पित्रोदा की मोदी से मुलाकात कराई थी। पित्रोदा ने अपनी टिप्पणी से भाजपा को सुर्खियां बटोरने का मौका दे दिया।

सपा-कांग्रेस गठबंधनः सीटों के पेच में उलझती सियासी राह

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर %इंडिया% गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है।

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के %बड़े भाई% की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवंबर की औपचारिक बैठक को तीन-चार दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी



हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है।

गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत चार फीसदी से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है।

अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है—%जिताऊ क्षमता%)। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है, और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई सहयोगी दल अपनी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से अधिक सीटों की जिद पकड़ लेता है और कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारता है, तो उसका सीधा लाभ विरोधी खेमे को मिलता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का कड़वा अनुभव दोनों दलों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। उस समय सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी गई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसका खामियाजा पूरे गठबंधन को सत्ता से दूर रहकर भुगतना पड़ा था। सपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि 2027 में 2017 की उस ऐतिहासिक भूल को दोहराया जाए। दूसरी ओर, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में केवल 50 या 60 सीटों पर सिमट जाती है, तो इससे न केवल राज्य के शेष हिस्सों में उसका संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उसके मनोबल और सौदेबाजी की ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां पिछली बार सपा के विधायक जीते थे या सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे स्थानीय स्तर पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपना स्वाभाविक है।

इस सियासी रस्साकशी के बीच यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान केवल दो ध्रुवों तक सीमित नहीं है। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने मजबूत बूथ प्रबंधन, सामाजिक इंजीनियरिंग और डबल इंजन सरकार की योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोटों का जरा सा भी बिखराव सपा और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह दोहराया है कि %इंडिया% गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। लेकिन शीर्ष नेताओं की यह सद्भावना तभी फलीभूत हो सकती है जब वह जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर तक पहुंचे। यदि सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही सूची लीक होने और एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास का संदेश जाएगा।

दरअसल अब 17 नवंबर की बैठक का टलना कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है। राजनीति को संभावनाओं और समझौतों की कला कहा जाता है। आने वाले दिनों में जब दोनों दलों की समन्वय समितियां आमने-सामने बैठेंगी, तो उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी और अहं के टकराव से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। कांग्रेस को यह स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की धुरी समाजवादी पार्टी ही है और उसकी सांगठनिक ताकत के बिना भाजपा को चुनौती देना असंभव है। वहीं, समाजवादी पार्टी को भी बड़े भाई का उदार हृदय दिखाते हुए कांग्रेस को इतनी सम्मानजनक हिस्सेदारी अवश्य देनी होगी, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक और अल्पसंख्यक मतदाता पूरे उत्साह के साथ गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सके। सीटों की इस बिसात पर यदि दोनों दल अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर केवल %जीत% के साझा लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से बात बन सकती है। अन्यथा, तालमेल की यह देरी और आपसी अविश्वास 2027 की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही विपक्ष की धार को कुंद कर सकता है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

उसके थोड़े ही दिन बाद (सातवीं सदी के अन्त या आठवीं के आरम्भ में) कुमारिल और शङ्कर ने बौद्ध धर्म पर तीव्र आक्रमण किया। बौद्धों की जनश्रुति के अनुसार कुमारिल धर्मकीत्ति के समकालीन थे और उन्होंने कुमारिल को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, परन्तु यह जनश्रुति प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती।

तिब्बत के बौद्ध साहित्य में महायान दर्शन के 6 महान् आचार्यों को जम्बूद्वीप (भारत) के छै रत्न कहा गया है। ये छै रत्न, नागार्जुन, आर्यदेव, असङ्ग, वसुबन्धु, दिङ्नाग और धर्मकीत्ति हैं।

यह स्पष्ट है कि इनमें पहिले दो नागार्जुन और आर्यदेव शून्यबाद के, अगले दो असङ्ग और बसुबन्धु (जो कि दोनों सगे भाई थे) विज्ञानवाद के, और अन्तिम दो दिङ्नाग और धर्मकीर्त्ति बौद्ध न्यायवाद के प्रवर्त्तक आचार्य हैं। न केवल बौद्ध दर्शन अपितु सारे भारतीय दर्शन को नागार्जुन और दिङ्नाग की मौलिक प्रतिभा ने दो सर्वथा नवीन विचारधारायें दीं और उस दृष्टि से वै दोनों नाम बौद्ध दर्शन में सर्वोपरि हैं।

परन्तु बौद्ध दर्शन साहित्य को सबले अधिक बहुमुखी देन वसुबन्धु की है और उस दृष्टि से उसका नाम सर्वोपरि है। केवल वसुबन्धु को ही द्वितीय बुद्ध कहे जाने का गौरव प्राप्त है।

दिङ्नाग और काण्टः इस ऐतिहासिक भूमिका के पश्चात दिङनाग के दर्शन के विषय में संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है।

जहाँ तक बौद्ध न्याय (Logic) का प्रश्न है, यद्यपि उस दिशा में दिङ्नाग से पहिले नागार्जुन, असङ्ग, वसुबन्धु आदि ने बहुत कुछ कार्य किया, परन्तु नियमित रूप से बौद्ध न्याय की स्थापना करने का श्रेय दिनाग को ही प्राप्त है।

क्रमशः ...

रानी लक्ष्मीबाई

ज्योति खरे

भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थीं। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थीं वीरांगना लक्ष्मीबाई।

महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत ताम्बे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक



होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से जानी जाती थीं। इधर सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विधुर थे। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने-कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई, लेकिन चार माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया।

सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे।

यद्यपि महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवनकाल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंगरेजी सरकार को सूचना दे दी थी। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लार्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तकपुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंगरेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पोलेटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, %मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी%। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंगरेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी व नगर के राजमहल में निवास करने लगीं।

यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंगरेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे-महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्णावसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंगरेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई।

नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दनसिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे।

क्वॉड और आसियान समिट में दुनिया ने माना मोदी डिप्लोमेसी का लोहा

नीरज कुमार दुबे

मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आसियान सम्मेलन और क्वॉड शिखर बैठक के बीच मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा की शुरुआत ही क्वॉड नेताओं के साथ बैठक से की। दो साल बाद हुई इस पहली क्वॉड शिखर बैठक में ट्रंप ने पहली बार इस समूह के नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की। इसके तत्काल बाद उनका चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संवाद प्रस्तावित है। ऐसे समय में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, चीन पर तकनीकी निर्यात प्रतिबंध, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर क्वॉड की एकजुटता प्रदर्शित करना विशेष रणनीतिक महत्व रखता है।

साथ ही इसी बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र, महान नेता और पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्तित्व बताते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा की। यह घटनाक्रम मोदी की कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित करता है। एक ही यात्रा में मोदी ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वॉड के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने, आसियान देशों के साथ आर्थिक एवं सामरिक सहयोग का विस्तार करने और फिलीपींस, थाईलैंड तथा सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत की उपस्थिति दर्ज कराई है। यह यात्रा दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल केवल औपचारिक मुलाकातों के लिए नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

जहां तक क्वॉड बैठक की बात है तो आपको बता दें कि ट्रंप ने इस दौरान मोदी को %टफ मैन%, %ग्रेट



लीडर% और अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी दुनिया में सम्मान है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को शानदार बताते हुए कहा कि दोनों देश करीबी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। देखा जाये तो यह महज औपचारिक प्रशंसा नहीं, बल्कि उस समय आया महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा के तहत चीन जाने वाले हैं और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। कूटनीतिक हलकों में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करने से पहले ट्रंप की मोदी से वार्ता को अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

साथ ही चीन जैसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौर से पहले ट्रंप का मोदी के प्रति सार्वजनिक सम्मान प्रदर्शित करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई संदेश देता है। पहला संदेश यह है कि अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखता है। दूसरा संदेश है कि चीन के साथ बातचीत की मेज पर बैठने से पहले अमेरिका अपने उन साझेदारों के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है, जो एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तीसरे संदेश में रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को साधने की अमेरिकी कोशिशों के बीच भारत की स्वतंत्र और प्रभावशाली विदेश नीति की अहमियत सामने आती है।

देखा जाये तो मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों की केमिस्ट्री इस कूटनीतिक समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर दिखाई देने वाला विश्वास भारत-अमेरिका संबंधों को राजनीतिक मजबूती देने में सहायक है। रक्षा, व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के सहयोग का व्यापक महत्व है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल व्यक्तिगत मित्रता से नहीं चलते, लेकिन जब व्यक्तिगत विश्वास के साथ रणनीतिक हित भी जुड़ जाते हैं, तो साझेदारी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं।

हम आपको बता दें कि मनीला में क्वॉड की बैठक भारत की कूटनीतिक सक्रियता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय रही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस रणनीतिक समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड को रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समुद्री सुरक्षा, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वॉड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।

मोदी ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष जनवरी से अब तक क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें हो चुकी हैं। यह चारों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खास बात यह है कि मोदी ने क्वॉड के एजेंडे को केवल चीन के प्रभाव को चुनौती देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और तकनीकी सहयोग का व्यापक स्वरूप दिया। यही मोदी की कूटनीति की विशेषता है। वह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग का रास्ता भी खुला रखते हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करते हैं।

इसके अलावा, 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को नई गति और गहराई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग से तय होना चाहिए। दोनों पक्ष दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी ने समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, युवाओं के आदान-प्रदान और आसियान देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा सहित नौ महत्वपूर्ण पहल प्रस्तावित कीं। वर्ष 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी उन्होंने साझेदारी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया।

साथ ही द्विपक्षीय मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री की सक्रियता दिखाई दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक और व्यापार पर चर्चा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के साथ रक्षा, निवेश, डिजिटल तकनीक और संपर्क बढ़ाने पर बातचीत हुई। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी का मनीला स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचना भी विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1901 में स्थापित यह फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। मोदी ने यहां अरदास में भाग लिया और गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी ने शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का समर्थन करने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद तथा साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत किसी एक शक्ति खेमे का हिस्सा बने बिना दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। ट्रंप का मोदी की प्रशंसा करना, क्वॉड में भारत की सक्रिय भूमिका और आसियान देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी बदलती वैश्विक स्थिति को रेखांकित करता है।

आज का इतिहास

1824 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बाढ़ से दस हजार लोगों की मौत।
1838 ब्रह्मसमाज के आध्यात्मिक नेता केशब चंद सेन का जन्म।
1895 फ्रेडरिक ई ब्लेसडेल ने पेंसिल का पेंटेट कराया।
1917 इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म।
1922 तुर्की के युवराज अब्दुल मजीद द्वितीय को खलीफा चुन लिया गया।
1933 यूरोपीय देश स्पेन में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला।
1951 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1952 स्पेन यूनेस्को का सदस्य बना।
1977 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात का ऐतिहासिक इस्राइल दौरा। यह किसी अरब नेता का पहला इस्राइल दौरा था। इस दौरान उन्होंने शांति स्थापना का प्रस्ताव पेश किया।
1982 नयी दिल्ली में नौवें एशियाई खेलों की शुरूआत। लंबे अर्से के बाद देश में विशाल पैमाने पर खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया।
1985 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के बीच पहली मुलाकात। दोनों जिनेवा में एक शिखर सम्मेलन के दौरान मिले।
1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ।
1994 भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गईं।
1995 कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया।
1997 कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
2000 पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की माँ नुसरत भुट्टो को दो वर्ष के कठिन कारावास की सज़ा सुनाई।
2005 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने भारत को भूकम्प पीड़ितों के हित में कश्मीर समस्या सुलझाने का सुझाव दिया।
2006 भारत ने परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा।
2007 अमेजन ने किताब पढ़ने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण किंडल की बिक्री शुरू की, जिसने ई-बुक्स को प्रचलित बनाने में बड़ा योगदान दिया।
2008 संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मो. अलबरदेई को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की गई।
2019 गोटबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

दुनिया में अशांति फैलाने वाले ट्रंप-पुतिन-शी करेंगे शांति की बात

नीरज कुमार दुबे

दुनिया में वैसे तो तमाम तरह के विरोधाभास देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियां खुद एक ऐसा कदम उठाने जा रही हैं, जिसे इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है। दुनिया को युद्ध, तनाव और टकराव की आग में झोंकने वाली ये तीनों ताकतें अब एक मंच पर बैठकर शांति और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस प्रस्तावित मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं, पुतिन लगभग पांच साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं और जिनपिंग ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी सैन्य और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यही तीनों नेता दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने के लिए एक साथ बैठेंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ इस बैठक के एजेंडे का नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उन सामरिक और रणनीतिक उद्देश्यों का भी है, जिनका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है।

देखा जाये तो हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं। ईरान के साथ सैन्य टकराव, अमेरिकी हमले और तेहरान के जवाबी पलटवार ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों की जान ली, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाया। ईरान को लेकर ट्रंप का लगातार बदलता रुख कभी सैन्य धमकियों, कभी अधिकतम दबाव और कभी बातचीत की पेशकश के रूप में सामने आता रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि शेनझेन में होने वाली बैठक ट्रंप की वास्तविक शांति पहल है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुखिया के रूप में अपना दबदबा स्थापित करने का एक और मंच है?

दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लगभग पांच साल पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहर तबाह हुए हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। जिस युद्ध को रूस ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सवाल बताकर शुरू किया था, वह अब वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन शांति की बातचीत में क्या प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे? क्या वह युद्ध समाप्त करने का रास्ता तलाशेंगे या अपनी सैन्य कार्रवाई से हासिल किए गए क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की



कोशिश करेंगे?

पुतिन के लिए इस बैठक का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर बैठना रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को नई वैधता और प्रतिष्ठा दे सकता है। देखा जाये तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से रूस को अलग-थलग करने की कोशिशों के बीच यह तस्वीर मॉस्को के लिए अपने आप में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी।

कथित शांति की चाह रखने वाले तीसरे खिलाड़ी शी जिनपिंग हैं। देखा जाये तो चीन एक तरफ खुद को वैश्विक शांति और सहयोग का समर्थक बताता है, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर उसकी सैन्य और राजनीतिक धमकियां लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ाती हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियां फिलीपींस, वियतनाम और अन्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। समुद्री क्षेत्रों पर दावेदारी, सैन्य ठिकानों का विस्तार और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें चीन की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती हैं। सवाल है कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में दबाव की राजनीति करने वाले जिनपिंग शेनझेन में किस तरह की शांति व्यवस्था की बात करेंगे? क्या चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है?

देखा जाये तो इस बैठक के मायने केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं हैं। इसके पीछे परमाणु हथियारों का संतुलन, वैश्विक सैन्य वर्चस्व, आर्थिक हित और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई भी छिपी है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी बातचीत में शामिल हो। रूस के साथ अमेरिका की पुरानी परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और वाशिंगटन अब बीजिंग को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन चीन के परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में जिनपिंग क्यों ऐसी बातचीत में शामिल होंगे जिसमें उनकी सामरिक बढ़त के बजाय उनकी शक्ति को सीमित करने पर चर्चा हो?

देखा जाये तो पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के साथ सीधे संवाद का रास्ता महत्वपूर्ण है, जबकि जिनपिंग के लिए यह साबित करने का अवसर है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच किसी भी नए वैश्विक समीकरण में चीन की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं ट्रंप के लिए यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव दिखाने का मौका है।

साथ ही इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की व्यवस्था अब तीन महाशक्तियों के आपसी समझौतों से तय होगी? क्या छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर भी इन तीनों की बातचीत का प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों की चिंता इसी वजह से बढ़ रही है। कहीं यह मुलाकात 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी किसी नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं बनने जा रही, जहां बड़ी ताकतें अपने हितों के अनुसार दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण करने लगें?

बहरहाल, तीन नेता, तीन महाशक्तियां और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़े कई बड़े सवाल सामने हैं। शांति की मेज पर आमने-सामने बैठने जा रहे इन तीनों नेताओं की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वे अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक वर्चस्व की होड़ से कितना पीछे हटने को तैयार हैं। क्या ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग दुनिया को शांति का नया रास्ता दिखा पाएंगे या उनकी यह मुलाकात भी महज कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी? अंत में एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि जो नेता अपने-अपने मोर्चों पर तनाव और टकराव की राजनीति कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में दुनिया को अशांति से बाहर निकालने का इरादा रखते हैं?

बंगाल की खाड़ी में 13 साल बाद मौसम का बड़ा बदलाव

कांतिलाल मांडोत

प्रकृति का मिजाज कब बदल जाए, इसका अनुमान लगाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी तेज गर्मी और कभी बेमौसम बारिश तो कभी अचानक आने वाले तूफान जनजीवन को प्रभावित कर देते हैं। इन दिनों बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसमी सिस्टम इसी बदलते मौसम की एक बड़ी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में तीन सप्ताह के भीतर तीसरा चक्रवाती तूफान बनने की आशंका जताई गई है। यदि यह सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो इसे अकवान नाम दिया जा सकता है। खास बात यह है कि करीब 13 साल बाद इतनी कम अवधि में बंगाल की खाड़ी में लगातार तीन चक्रवाती तूफान बनने की स्थिति सामने आ रही है। मौसम में इस असामान्य बदलाव ने मौसम वैज्ञानिकों के साथ-साथ तटीय राज्यों की सरकारों की चिंता भी बढ़ा दी है। बंगाल की खाड़ी में रविवार को एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होकर डिप्रेशन में बदल गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम आगे बढ़ते हुए सोमवार तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और 17 नवंबर तक इसकी तीव्रता गंभीर चक्रवाती तूफान जैसी हो सकती है। फिलहाल इसका सटीक रास्ता और समुद्र तट से टकराने का स्थान तय नहीं हुआ है। अगले 24 घंटों में इसकी दिशा और प्रभाव को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2013 में भी बंगाल की खाड़ी में नवंबर और दिसंबर के दौरान लगातार चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिली थीं। उस वर्ष 19 नवंबर को हेलेन, 23 नवंबर को लहर और 6 दिसंबर को माडी नाम के तूफान बने थे। इससे पहले अक्टूबर में फाइलिन तूफान ने भी इसी क्षेत्र में दस्तक दी थी। इस तरह कुछ ही महीनों में चार बड़े तूफानों का बनना मौसम के लिहाज से असामान्य घटनाक्रम था। अब 13 साल बाद एक बार फिर कम समय में लगातार तूफान बनने की आशंका ने मौसम के बदलते स्वरूप पर चर्चा शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफानों का प्रभाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता। इनका असर तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ अंदरूनी इलाकों में भी देखने को मिलता है। तेज हवाएं, भारी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरें और निचले क्षेत्रों में पानी भरने जैसी समस्याएं आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से मछुआरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और समुद्र के किनारे रहने वाले परिवारों के लिए ऐसे तूफान बड़ी चुनौती बन जाते हैं। कई बार खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और बिजली, सड़क तथा संचार व्यवस्था भी प्रभावित होती है। संभावित तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता जारी कर दी है। तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों में बचाव तथा राहत की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी मौसम विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि समय रहते लोगों तक सही सूचना पहुंचे और किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्य तुरंत शुरू किए जा सकें। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना चाहिए। समुद्र में पहले से मौजूद नावों को सुरक्षित स्थानों पर लौटने की सलाह दी जानी चाहिए। ऐसे समय में आम नागरिकों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। तूफान आने से पहले घरों की छत, खिड़कियों और दरवाजों की जांच कर लेनी चाहिए। घर के बाहर रखे गमले, कुर्सियां, टीन और दूसरी हल्की वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, ताकि तेज हवा में वे किसी के लिए खतरा न बनें। घर के आसपास सूखी और कमजोर शाखाओं वाले पेड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। बिजली की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, सूखा भोजन और जरूरी दवाइयां पहले से रखनी चाहिए। मोबाइल फोन चार्ज रखना और परिवार के सभी सदस्यों को आपात स्थिति की जानकारी देना भी समझदारी है।

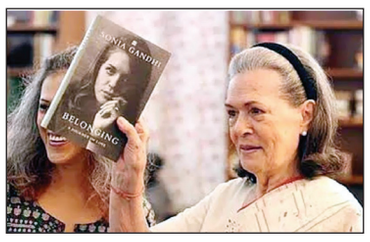
सोनिया गांधी ने अपने जीवन की एक खिड़की खोली है

कल्याणी शंकर

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इर्द-गिर्द क्या रहस्य है? वह 1968 में एक युवा दुल्हन के रूप में भारत आई थीं और सार्वजनिक जीवन में कई वर्षों के बाद भी, बहुत कम लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। वह एक निजी व्यक्तिगत जीवन बनाए रखती हैं, जिससे उनकी प्राथमिकताओं, भारत के लिए दृष्टिकोण और विभिन्न मुद्दों पर विचारों के बारे में कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। कुछ लोग उन्हें एक पहेली के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें अहंकारी मानते हैं या 'ऑरबासैनो की सिंड्रेला' कहते हैं। धारणाएं जो भी हों, वह एक असाधारण महिला साबित हुई हैं, जिसका बहुत सा श्रेय भारत में अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण करने के उनके प्रयासों को दिया जाता है।

सोनिया गांधी की राजनीतिक उपस्थिति और व्यक्तिगत कहानी जनता के ध्यान को आकर्षित करती है। अमरीकी दूतावास के एक टैलीग्राम ने उनकी भारतीय छवि और उनके मूल इतालवी व्यक्तित्व के अनूठे मिश्रण पर प्रकाश डाला था, जो उनके गर्मजोशी से भरे और निजी स्वभाव को दर्शाता है। उनकी हालिया किताब, 'बिलॉन्गिंग', इसके प्रकाशक पेंगुइन द्वारा इसे वापस लेने के विवाद के बाद जारी की गई थी, जिसके बाद हार्परकोलिन ने इसे प्रकाशित किया। यह पुस्तक आत्मकथा और राजनीतिक टिप्पणी का मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो इटली में एक युवा लड़की के रूप में और बाद में गांधी परिवार के भीतर उनके जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

यह उनकी भाभी मेनका गांधी के अनुभवों, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, आर.एस.एस. और विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर उनके विचारों



की पड़ताल करती है। सोनिया कहती हैं, ''कई मायनों में, यह किताब उनकी मानवता के प्रति एक श्रद्धांजलि है। मेरी कहानी पाठकों को एक अनूठा दृष्टिकोण भी प्रदान करती है।'' वह उस खूबसूरत देश में 6 दशकों के दौरान देखे गए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का वर्णन करती हैं, जिससे वह जुड़ी हुई हैं। 10 नवम्बर को जारी 544 पन्नों का यह संस्मरण, युद्धोत्तर इटली और कैम्ब्रिज से भारतीय राजनीति तक सोनिया गांधी की यात्रा का विवरण देता है। यह 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए राजीव गांधी की शुरुआती अनिच्छा को रेखांकित करता है।

1946 में मिलान, इटली में एक साधारण परिवार में जन्मी सोनिया का शुरुआती जीवन उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं से भरा था, जो उस राजनीतिक उथल-पुथल के बिल्कुल विपरीत था, जिसका उन्हें बाद में सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, ''वह हृदयविदारक दुख और क्षति ही थी जिसने मुझे राजनीति के सार्वजनिक क्षेत्र में धकेला। उस समय तक, मैंने अपनी निजता की सख्ती से रक्षा की थी।''उनकी कथा उनके बचपन से शुरू होती है, यह दर्शाती है कि कैसे उनके पालन-पोषण ने उनमें एक मजबूत कार्य नैतिकता की नींव रखी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वह राजीव गांधी से मिलीं, एक ऐसी मुलाकात, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह पुस्तक एक विदेशी देश की एक युवा लड़की से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दलों में से एक की नेता बनने तक की उनकी परिवर्तनकारी यात्रा की रूपरेखा तैयार करती है। सोनिया की 1968 की शादी ने भारतीय राजनीति में उनके प्रवेश को चिन्हित किया और उनकी शुरुआती अनिच्छा और सांस्कृतिक मतभेदों के साथ संघर्ष उनकी कहानी में स्पष्ट हैं। वह इंदिरा गांधी के घर में बिताए जीवन और भारतीय पारिवारिक जीवन में ढलने के अपने प्रयासों को याद करती हैं, जिसमें मसालेदार भोजन संभालना भी शामिल है। वह विशिष्ट व्यंजनों का उल्लेख करती हैं, जैसे कूर्मा की एवोकैडो करी और विभिन्न मसालेदार सब्जियां।

1991 में राजीव गांधी की हत्या पर उनके विचार एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाते हैं। उनकी अचानक हुई क्षति ने उन्हें जनता की नजर में ला खड़ा किया और उन्हें अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर किया। वह विचार करती हैं कि राजीव 'एक चुभती हुई अनुपस्थिति की बजाय मेरे भीतर एक उपस्थिति बन गए।' जब दलाई लामा ने उनसे अपने पति के हत्यारों के प्रति प्रतिशोध की भावना महसूस करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, ''नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती।'' यह पुस्तक उनके गहन शोक और उस सहनशक्ति को चित्रित करती है जो उन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए पाई। उन्होंने दुख को ताकत में बदला और एक नेता के रूप में उभरीं। सोनिया को अपने कई सवालों के 'उत्तर' भगवद् गीता में मिले। यद्यपि वयस्कता में वह धार्मिक नहीं थीं, फिर भी उन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए 1997 में एक संस्कृत विद्वान से निजी शिक्षा ली। बिना किसी लगाव के अपने कर्त्तव्य का पालन करने के गीता के संदेश ने उनके साथ गहरा तालमेल बिठाया, जिससे उन्हें आंतरिक संघर्षों को सुलझाने में मदद मिली। उनकी कथा में एक प्रमुख विषय नेतृत्व में सहनशक्ति और सहानुभूति का महत्व है।

विभिन्न समुदायों के साथ सोनिया के प्रत्यक्ष अनुभव शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। वे जमीनी स्तर की राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिसमें कई कहानियां आम लोगों के साथ उनकी बातचीत को प्रदर्शित करती हैं। यह पुस्तक भारतीय राजनीति की जटिलताओं की छानबीन करती है, जो बदलते गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता की विशेषता है। सोनिया ने इन चुनौतियों को व्यावहारिकता और आदर्शवाद के साथ नेविगेट किया लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार करने या अपने दोनों बच्चों को राजनीति में शामिल करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया।

कांग्रेस पार्टी के इतिहास और भविष्य पर अपने विचारों में, सोनिया समकालीन मुद्दों का एक सामयिक राजनीतिक विश्लेषण प्रदान करती हैं। हालांकि, वह भोपाल गैस त्रासदी और वॉरेन एंडरसन के भागने के संबंध में चुप रहती हैं। वह शाहबानो मामले पर चर्चा करती हैं, जिसमें राजीव द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती दिए बिना उनकी और वैसी ही महिलाओं की सहायता करने के इरादे पर प्रकाश डाला गया है।

सोनिया ओटावियो क्वात्रोची का उल्लेख करने से भी बचती हैं और राजीव के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसमें 2004 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसने उन्हें खारिज कर दिया था, जबकि यह ध्यान दिलाया गया है कि 'बोफोर्स' राजनीतिक विपक्ष के लिए एक उपकरण बना हुआ है।

भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र

ललित गर्ग

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13-14 नवंबर 2026 को आयोजित 'भारत समिट' इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों-जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे 'एंटी-भारत समिट' तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है-क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं।



यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और 'वोट चोर-गद्दी छोड़' जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए?

लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति-भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए-क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को 'भारत विरोधी' या हर आलोचना को 'विदेशी साजिश' बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं।

इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण-सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है-विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे।

उत्तरप्रदेश में भाजपा के सामने 'वाटरलू'

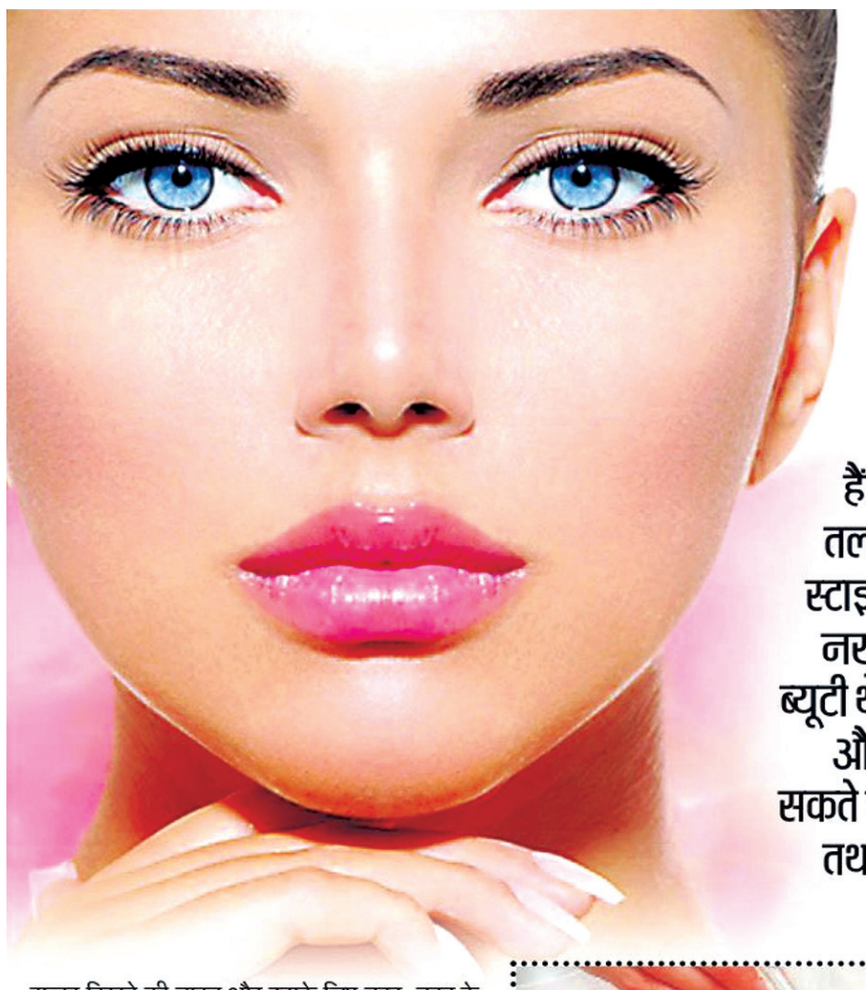
हरीश गुप्ता

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले ही सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची कर रही हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने भी अपने गठबंधन को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब उसके साथ चार सहयोगी दल हैं और सभी को संतुष्ट करना राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। पहले संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) इसके सहयोगी थे। बाद में जयंत चौधरी की आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी गठबंधन में शामिल हो गईं, जिन्होंने 2022 में सपा के साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भाजपा, जिसने 2022 में 376 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, कम से कम 350 सीटें चाहती है और 53 सीटें अपने सहयोगियों को देना चाहती है। वहीं, आरएलडी 30 सीटें और निषाद पार्टी 15 सीटें चाहती है। इन दोनों की मांगों के कारण भाजपा को मुश्किल से 330 सीटें ही मिल पाएंगी। सहयोगी दलों को लग रहा है कि पेपर लीक, राम मंदिर के चंदे और पार्टी के अंदरूनी विवादों को लेकर भाजपा कमजोर स्थिति में है। इसलिए वे अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। भाजपा को गैर-यादव ओबीसी वोटों को एकजुट रखने के लिए इन सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन परेशानी यह है कि सहयोगी दल भी समझ रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में उनकी सौदेबाजी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

24 घंटे में मंत्री का यू-टर्न: केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पिछले दिनों एक दिन पहले दिए गए अपने बयान से जल्द ही पलटी मार ली। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि सरकारी योजनाओं के तहत कल्याणकारी भुगतान के लिए



आधार की जगह एपिक नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बयान से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और माकपा ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों के कल्याणकारी अधिकारों को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने इससे भी तीखा हमला करते हुए इसे 'हक चोरी' करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही राशन, पेंशन, मनरेगा के भुगतान और छात्रवृत्ति हासिल करने के लिए वोटर आईडी को अनिवार्य प्रवेश द्वार बनाया जा सकता है। इसके बाद मंत्री ने तुरंत अपना रुख बदल लिया और घोषणा की कि वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए एपिक और आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह आधार की वापसी हो गई, लेकिन एपिक को भी व्यवस्था में शामिल रखा गया। इसे राजनीतिक यू-टर्न कह सकते हैं, वह भी ब्रेकिंग न्यूज की रफ्तार से। मंत्री को समझ में आ गया कि कल्याणकारी योजनाओं के नियमों में बदलाव करना कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल।



खूबसूरत दिखना हर कोई चाहता है। लोगों की यही चाहत ऐसे बहुत से रोजगार पैदा कर जाती है, जिसकी आमतौर पर सामान्य छात्र कल्पना नहीं करता। कॉस्मेटोलॉजी ऐसा ही क्षेत्र है। इसमें अनेक शाखाएं हैं, जहां भविष्य की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आप हेयर स्टाइलिस्ट, शैम्पू टेक्नीशियन, नख प्रसाधक, इस्थेटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रोलॉजिस्ट तक बन सकते हैं और जॉब के रूप में हजारों तथा खुद का काम करके लाखों कमा सकते हैं।



सौन्दर्य के संसार में खूबसूरत करियर

सुन्दर दिखने की चाहत और उसके लिए तरह-तरह के नुस्खों की आजमाइश जोरों पर है। इसके लिए बाजार में सौन्दर्य प्रसाधनों व लाइफ स्टाइल के उत्पादों की बाढ़ सी आ गई है। शेविंग क्रीम हो या टूथ पेस्ट, फेस क्रीम, स्क्रीन क्रीम या फिर शैम्पू, साबुन और तेल-ये सभी आम जीवन की जरूरतों में शामिल हैं। बाजार में रोजमर्रा की मांग ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी खूब पैदा किए हैं। कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स इन अवसरों के बीच ही ले जाता है। इसकी मांग को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इस कोर्स को करवाया जा रहा है।

कॉस्मेटोलॉजी के रंग

इस कोर्स में छात्रों को पहले कॉस्मेटोलॉजी की विभिन्न ब्रांच और उसके विविध रूपों की जानकारी दी जाती है। ये ब्रांच हैं हेयर स्टाइलिस्ट, शैम्पू टेक्नीशियन, नख प्रसाधक, इस्थेटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रोलॉजिस्ट। इसके बाद इन क्षेत्रों में काम आने वाले विभिन्न प्रोडक्ट्स के निर्माण के बारे में बताया जाता है। मसलन शेविंग क्रीम, टूथ ब्रश, पेस्ट, फेस क्रीम, सन्सक्रीम, नेल पॉलिश आदि। कोर्स से जुड़े विशेषज्ञों की मानें तो लाइफ स्टाइल और सौन्दर्य प्रसाधन से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट प्रचलन में हैं, चाहे वे त्वचा संबंधी हों या आंख, नाक, कान, बाल, मुंह या शरीर के किसी और अंग से, इन सबके बारे में इस कोर्स में बताया जाता है। हेयर स्टाइलिस्ट को बालों के विभिन्न रूप, उनकी कटिंग और उनमें काम आने वाले कैमिकल्स की जानकारी दी जाती है। बालों को सुंदर बनाने की कला से भी रूबरू कराया जाता है।

शैम्पू टेक्नीशियन को आमतौर पर शैम्पू बनाने की विधियां, उसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन और उसके इस्तेमाल की तरकीबें बताई जाती हैं। नख प्रसाधन के क्षेत्र में हाथ और पैर को सुन्दर बनाने वाली पॉलिश और क्रीम आदि के बारे में बताया जाता है। साथ ही देखभाल के बारे में जानकारी दी जाती है।



इस्थेटिशियन को आमतौर पर त्वचा की देखभाल की कला सिखाई जाती है। उसे नई तकनीक के इस्तेमाल से अंग लेपन, फेशियल मसाज आदि से अवगत कराया जाता है। इसमें दक्ष इस्थेटिशियन चाहे तो स्वतंत्र रूप से सैलून या स्पा में काम कर सकता है। वह चाहे तो किसी डॉक्टर को इस क्षेत्र की प्रैक्टिस में सहायता भी प्रदान कर सकता है। इस्थेटिशियन को त्वचा की देखभाल संबंधी उत्पाद की जानकारी के साथ-साथ उसके नफे-नुकसान के बारे में बताया जाता है। त्वचा की पूरी तरह से देखभाल के कारण इसे स्किन केयर थेरेपिस्ट भी कहा जाता है।

ब्यूटी थेरेपिस्ट को मशीन द्वारा बालों को हटाना, आंखों की पुतलियां सजाना, ठीक करना जैसी चीजों के बारे में दक्ष बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलॉजिस्ट को इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। विद्युत तरंगों से लैस मशीन से बाल को उखाड़ना या उसे उगाना जैसे काम इसमें बखूबी किए जाते हैं। कोर्स में छात्रों को सामान्य मेडिसिन की जानकारी भी दी जाती है। हालांकि डॉक्टर की तरह इलाज करना उसका काम नहीं होता। उसे सौन्दर्य प्रसाधन से जुड़े प्रोडक्ट्स का क्या-क्या असर होगा, यह भी पढ़ाया जाता है। मोटापा बढ़ने पर वजन कम करने और आकर्षक लुक व सुडौल शरीर कैसे बने, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। यही नहीं, उसे मानव साइकोलॉजी का भी पाठ पढ़ाया जाता है। कोर्स में एनेलिटिकल कैमिस्ट्री का भी पाठ शामिल है।

दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले के लिए कहीं 12वीं पास तो कहीं बीएससी या स्नातक की मांग की जाती है। कैमिस्ट्री की पढ़ाई करने वालों के लिए यह और फायदेमंद हो जाता है। यह कोर्स सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह के संस्थानों में चल रहे हैं।



रोजगार कहां

कोर्स को करने के बाद छात्र चाहे तो खुद बॉडी केयर सेंटर खोल सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में इस तरह के सेंटर से लोग प्रति माह हजारों रुपए कमा रहे हैं। आप ब्यूटीशियन के लिए बतौर कंसलटेंट काम कर सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में भी काफी अवसर हैं। छात्र चाहे तो कॉस्मेटिक निर्माण की यूनिट भी लगा सकता है। जहां तक आय का सवाल है, कोई चाहे तो किसी के यहां काम करके 20 से 30 हजार रुपए भी कमा सकता है और स्वरोजगार में लाख, दो लाख रुपए महीना भी।

क्या कहता है आपका एप्टीटयूड



विषय अनेक और करियर भी अनेक, इतने कि किसे चुनें, किसे नहीं। इसी ऊहापोह में छात्र भटक कर रह जाते हैं। अपनी दुविधा लेकर काउंसलरों के पास आने वाले छात्रों के आंकड़े बताते हैं कि हाल-फिलहाल में छात्रों में यह असमंजस की स्थिति कहीं ज्यादा बढ़ी है। आपके इस असमंजस को सही दिशा दे सकता है एप्टीटयूड टैस्ट। किस-किस तरह के हैं ये एप्टीटयूड टैस्ट?

अमोल संगीतज्ञ बनना चाहता है, लेकिन उसके माता-पिता उसे इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं। पिता और अमोल के बीच करियर के चुनाव को लेकर काफी दिन तक खींचतान चलती रही। घर में इस कलह को दूर करने के लिए उसे काउंसलरों ने एप्टीटयूड टैस्ट कराने की सलाह दी। अमोल के एप्टीटयूड टैस्ट के बाद ही यह पता लगाया गया कि वह एक सफल संगीतज्ञ बन सकता है। टैस्ट में उसमें क्रिएटिव इनोवेशन के लक्षण ज्यादा पाए गये। इस क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि भी देखी गई। अमोल अकेला ऐसा छात्र नहीं। उसकी तरह कई और भी छात्र हैं, जिनके जीवन को सही दिशा देने के लिए माता-पिता अब एप्टीटयूड टैस्ट कराने लगे हैं। किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन एप्टीटयूड टैस्ट से ही हो पाता है। उसमें इंजीनियर बनने की क्षमता है या ड्राइवर या कलाकार, इसे पता लगाने का सटीक उपाय है एप्टीटयूड टैस्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रो. एनके चड्ढा कहते हैं, करियर का सही चुनाव और उसमें मौजूद क्षमता के आकलन के लिए एप्टीटयूड के साथ बच्चे की रुचि भी देखी जाती है। ऐसा करने पर करियर के चुनाव में खासी मदद मिलती है। एप्टीटयूड और इंटरेस्ट, दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं और साथ-साथ चलते हैं। अगर एक है और दूसरा नहीं तो करियर को सही दिशा नहीं मिलती।

काउंसलर गीतांजलि कुमार करियर और जीवन को सही दिशा देने में एप्टीटयूड और इंटरेस्ट के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व और शारीरिक क्षमता को भी एक कड़ी मानती हैं। वह कहती हैं, इन सबको मिला कर ही किसी को करियर या जीवन में कोई राह चुनने की सलाह दी जाती है। अगर किसी में किसी कार्य के प्रति एप्टीटयूड है, पर रुचि या करने की इच्छा नहीं तो उस दिशा में भेजना बेकार है। इसी तरह पहली दोनों चीजें हैं, लेकिन शारीरिक क्षमता या व्यक्तित्व नहीं तो ऐसे करियर के चुनाव की सलाह देना बेकार है। वह कहती हैं, व्यक्तित्व भी पॉजिटिव मोटिव देता है, इसलिए तीनों को देखना जरूरी है।

क्यों है जरूरी

एप्टीटयूड टैस्ट ही किसी छात्र या व्यक्ति के करियर और काम की दिशा बताता है। उसकी क्षमता और रुचि को बताता है। इसके बाद उसे सही प्रोफेशन चुनने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो अमुक व्यक्ति में आगे चल कर कुंठा का जन्म होता है। वह काम को एन्जॉय नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसके अंदर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। वह विध्वंसात्मक दिमाग का हो जाता है। उसमें पहचान का संकट भी पैदा होने लगता है। एप्टीटयूड, रुचि और व्यक्तित्व के हिसाब से काम नहीं मिलने पर वह अपने पेशे में उतना सक्षम साबित नहीं होता, जितना दूसरे लोग। ऐसे में वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कई बार उलटे-सीधे हथकंडे भी अपनाता है। सफलता नहीं मिलने पर वह कई बार अवसाद की स्थिति में आ जाता है और आत्महत्या को मजबूर हो जाता है, इसलिए शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बच्चों के करियर की दिशा तैयार करने को कहा है। शिक्षण संस्थाओं में करियर एंड काउंसलिंग सेंटर आए दिन इसी वजह से खोले जा रहे हैं। यह हर संस्थान और काम की जगह की जरूरत बनती जा रही है। प्रो. चड्ढा कहते हैं, भारत में इस तरह की समस्याओं के लिए निजी प्रैक्टिशनर की ओर से जगह-जगह नगरों व महानगरों में काउंसलिंग सेंटर खुल गए हैं, लेकिन इसे चलाने वाले लोग आमतौर पर क्वालिफाइड नहीं होते। काउंसलिंग के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए नेशनल एजेंसी बनी है। वह क्वालिफिकेशन तय करती है। गाइडलाइंस भी तैयार किए हैं।

एप्टीटयूड टैस्ट के रूप-रंग

लॉजिकल रीजनिंग- एप्टीटयूड टैस्ट के कई आयाम हैं, जिनमें एक है लॉजिकल रीजनिंग। इसके तहत कार्य-कारण संबंध पर जोर होता है। किसी व्यक्ति में मानसिक स्तर पर कैलकुलेशन की क्षमता कितनी है, इसका आकलन लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से किया जाता है। अगर वह लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा स्कोर करता है तो इससे पता चलता है कि वह कायदे-कानून में रह कर कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। इस क्षमता से लैस युवा मैनेजर, वैज्ञानिक और व्हाइट कॉलर जॉब में जाने के उपयुक्त होते हैं।

एब्सट्रेक्ट रीजनिंग - इसके तहत खरा उतरने वाला युवा बिखरी हुई चीजों को एकत्रित करके प्लान के साथ काम करने में विशेष हुनर रखता है। इसमें एप्टीटयूड किस तरफ जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, वह एक एरिया से दूसरे एरिया में लिंक कर रहा है या नहीं, यह भी देखा जाता है। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बेहतर करने वाले युवाओं में एब्सट्रेक्ट रीजनिंग हल करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है।

न्यूमेरिकल रीजनिंग - यह किसी व्यक्ति की गणितीय क्षमता की जानकारी देता है। वह गुणा-भाग करने और सांख्यिकीय सवालों को हल करने की कितनी क्षमता रखता है, इसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। इसे देख कर ही उसे इस विषय या क्षेत्र से जुड़े करियर में जाने की सलाह दी जाती है। मसलन सीए, गणितज्ञ और लेखाकार आदि बनने के लिए न्यूमेरिकल रीजनिंग में बेहतर होना चाहिए।

आई-हैंड कोऑर्डिनेशन - आमतौर टेक्निकल काम मसलन ड्राइविंग हो, पायलट या फिर किसी मशीन को चलाने के लिए मशीनमैन हो, उसमें यह एप्टीटयूड जरूर होना चाहिए। इसमें कोई व्यक्ति हाथ, पैर व आंख को काम करते वक्त कितना केन्द्रित कर पाता है, यह देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति दुर्घटनाओं को कम करने में काफी मददगार साबित होता है। ड्राइवर, पायलट, मशीनमैन और मैकेनिकल जॉब के लिए यह एप्टीटयूड बढ़िया माना जाता है।

क्रिएटिव इनोवेशन - इसमें किसी व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता का आकलन किया जाता है। उसमें कलात्मक रुझान व रुचि का पता लगाया जाता है। आमतौर पर व्हाइट कॉलर जॉब में इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके तहत यह भी देखा जाता है कि वह निर्णय कितना शीघ्र और सही रूप में लेता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति स्वभाव में अड़ियल तो नहीं है। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्तर बेहतर है तो उसे उच्चतम पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें उसके अंदर बड़प्पन कितना है, इसका आकलन भी किया जाता है। एप्टीटयूड टैस्ट में ओरिजनेलिटी और मौलिकता को भी देखा जाता है। ऐसे चंद ही व्यक्ति होते हैं, जो अलग किस्म के आइडिया से लैस होते हैं। इस टैस्ट में ओरिजनल आइडिया को देखा व समझा जाता है। इसे बहुविध सोच के रूप में भी देखा जाता है। यह गुण जिसमें है, उसमें अध्यापक, लेखक, अभिनेता, संगीतज्ञ और आविष्कारक बनने की क्षमता होती है।



प्रोफेशनल लाइफ में रख रहे हैं कदम अपनाएं ये टिप्स

कॉलेज लाइफ को अलविदा कहकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखने कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। कई युवाओं के लिए कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा होने और अपने पहले जॉब की शुरुआत काफी तनावपूर्ण होती है। कॉलेज पूरा करने के बाद आपको जॉब हंटिंग, इंटरव्यू देना होता है और वास्तविकता का सामना करना इतना आसान नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट से एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉई बनने का यह ट्रांजिशन सफल बनाने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। इन मुद्दों को समझकर और उनके लिए तैयार रहकर इस बदलाव को आसान बना सकते हैं।

कॉलेज जाने और नौकरी पर जाने में बहुत फर्क है। आप जॉब में बंक नहीं मार सकते। आप पैसे देकर ट्यूशन नहीं ले रहे बल्कि आपको पे किया जा रहा है। इसलिए ट्यूशन की तरह मन न होने पर आप काम पर नहीं जाने का मन नहीं बना सकते। आपको नौकरी में आठ घंटे तो काम करना ही पड़ता है।

कॉलेज का समय प्रयोग का समय होता है। हम यहां थोड़ा गैर जिम्मेदार हुए तो चलेगा लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं है। कॉलेज में गैर जिम्मेदार होने का मतलब खराब ग्रेड लेकिन वर्कप्लेस पर अनप्रोफेशनल होना मतलब आपके नौकरी की छुट्टी। प्रोफेशनल का मतलब ही सेल्फ-स्टार्टर होता है। कॉलेज से ज्यादा डेडलाइन का सामना आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में करना होगा।

ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके दिमाग में अपना स्पष्ट करियर पाथ होना चाहिए लेकिन अगर आपका पहला जॉब अपनी योजना से मेल नहीं खाता है तो घबराइए नहीं।

कॉलेज छोड़ने और प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने में बहुत चीजें बदलती है। हां, अगर आप दोपहर तक सोते रहते हैं या देर रात फिल्में देखते हैं तो यह सब आपको बंद करना पड़ेगा। आपकी डाइट भी बदलेगी। लाइफस्टाइल के बदलावों के लिए तैयार रहें।

कॉलेज लाइफ खत्म होने का मतलब नहीं कि आपकी लाइफ से फन गायब हो गया। आप अभी भी ट्रेवल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और नए व रोमांचक चीजें सीख सकते हैं। इस समय आपको देखना होगा कि किस तरह से मनोरंजन करें ताकि आप अपनी जॉब की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा पाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

2027 में सिर्फ हैट्रिक नहीं लगेगी रिकॉर्ड भी बनेगा : सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। हैट्रिक ही नहीं लगेगी, यह रिकॉर्ड भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, भाजपा के करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की शक्ति और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के दम पर पार्टी जनता के बीच जाएगी और जनता-जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। एक निजी चैनल के राइजिंग भारत समिट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पूरी दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई पहचान पर जिसे भी गौरव की अनुभूति होती है, वह भाजपा सरकार को तीसरी बार मौका देगा। उन्होंने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वह प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पांच वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर चुनाव जीता और दोबारा पांच वर्ष तक अपनी सरकार लगातार चलाई।

शिवसेना ने सोनिया की पुस्तक के पन्ने फाड़कर जताया विरोध

मुंबई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ता जा रहा है। वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर शिवसेना ने विरोध जताया और किताब की पन्ने फाड़े। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम और राष्ट्रीय सचिव शाइना एनसी ने मुंबई में बयान जारी कर किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। शिवसेना नेताओं ने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पेज नंबर 201 और 443 हटाने की मांग की है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर पहले भी बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। उनके मुताबिक, उस समय संसद में विरोध हुआ था और इसका असर मुंबई तक पहुंचा था। निरुपम ने बालासाहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मन में सावरकर के प्रति बहुत सम्मान था। उन्होंने दावा किया कि शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बालासाहेब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल मारी थी।

कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर पिनरायी विजयन का हमला

तिरुवनंतपुरम। केरलम विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनरायी विजयन ने बुधवार को कहा कि जबरन वसूली के मामले में कांग्रेस पदाधिकारी की गिरफ्तारी से पार्टी की सड़ चुकी राजनीतिक संस्कृति का घिनौना चेहरा उजागर हुआ है। विजयन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि यह इस सोच को दर्शाता है कि सत्ता मिलने पर कुछ भी किया जा सकता है और हर गलत काम को राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सड़ चुकी राजनीतिक संस्कृति का घिनौना चेहरा उजागर हो गया है। माकपा के वरिष्ठ नेता विजयन तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के सचिव सुहैल शाजहान की गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे थे। शाजहान पर एक डॉक्टर से 10 लाख रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर अस्पताल के बारे में मानहानिकारक वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में इटली के नेता के वीडियो हटाने की मांग

नई दिल्ली। इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इन वीडियो में फिलिबेक कथित तौर पर हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव फिलिबेक ने भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि मामले की सुनवाई के समय संबंधित पीठ के सामने विस्तार से दलीलें रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम की अंतरिम जमानत पर रोक से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मौखिक रूप से इस मामले का जिक्र किया और बुधवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की। एएसजी ने हाईकोर्ट की इस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या संबंधित अधिकारी को पक्ष बनाए बिना ऐसी टिप्पणी की जा सकती है? एएसजी ने कहा, यह आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया। हमें पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। यह सुनवाई के पहले ही दिन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि यह अंतरिम आदेश एक अंतिम आदेश की तरह है।

नेता प्रतिपक्ष पर भाजपा का तीखा हमला

भारत के मीर जाफर हैं राहुल विदेश में देश को बदनाम कर रहे

नई दिल्ली। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में एक साजिश के तहत भारत को बदनाम करने के लिए अनर्गल बयान, झूठे वक्तव्य और बेबुनियाद बातें कहते हैं, जिससे देश का हर नागरिक आज शर्मसार है।

उन्होंने कहा कि अराजकता के प्रतीक, अपरिपक्व, भारत से नफरत करने वाले राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, तो झूठे बयान देते हैं। उनकी मंशा भारत की प्रगति को ठेस पहुंचाना और भारत की मजबूत अंतरराष्ट्रीय छवि को कमजोर करना है। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, यह हर कोई जानता है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष होते हुए वे विदेशी धरती पर ऐसे जहरीले बोल बोलते हैं, तो पता चलता है कि वे भारत विरोधी हैं, एक शातिर व्यक्ति हैं और भारत के मीर जाफर हैं। जब भी संसद का सत्र होने वाला होता है, राहुल गांधी जरूर विदेशी धरती पर जाते हैं। क्या यह इसलिए है कि वे अपने विदेशी आकाओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें?



इससे पहले भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को भारत विरोधी प्रचार का नेता बताते हुए आरोप लगाया कि वह विदेश जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और लोकतंत्र को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है।

प्रदीप भंडारी ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वह विदेश दौरों पर हमेशा भारत के राष्ट्रीय हितों और तिरंगे के सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की तुलना पीएम मोदी के व्यवहार से की।

भंडारी ने एक वीडियो भी साझा किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि क्वाड जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जमीन पर गिरा भारतीय झंडे का निशान देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था।

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता देश लौटने के बाद भी विदेशी लोगों के जरिए भारत की व्यवस्था पर सवाल उठवाते हैं। भंडारी ने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को 2029 के आम चुनाव में भी विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा।

दरअसल, राहुल गांधी इन दिनों दो दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। यहां उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है और शिक्षा व्यवस्था के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि देश के मध्यवर्गीय परिवारों से आने वाले कई युवा मौजूदा हालात से निराश हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं।

चुनाव आयोग की टीम आज आगरा में

परखेगी उत्तरप्रदेश की चुनावी तैयारियां

नईदिल्ली। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 19 नवंबर को आगरा में उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह समीक्षा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल की शुरुआत में संभावित विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में आयोग का दल हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में जमीनी स्तर पर चुनावी तंत्र की तैयारियों का जायजा लेने मेरठ गया था। राज्य में समीक्षा का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आयोग उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब का दौरा पूरा कर चुका है, जबकि गोवा का दौरा प्रस्तावित है।

निर्वाचन आयोग ने हाल में 17 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश देते हुए कहा था कि इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले



भी चुनाव करा सकता है। चुनावी तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश और गोवा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) इकाइयों की प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) भी शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर उनमें तकनीकी खामियों की जांच करते हैं।

खराब मशीनों को मरम्मत या बदलाव के लिए निर्माताओं के पास भेजा जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 'मॉक पोल' (छद्म मतदान) भी कराए जाते हैं। एफएलसी के दौरान पिछला चुनावी डेटा भी मशीनों से हटा दिया जाता है।

जांच में सफल मशीनों पर 'एफएलसी ओके' का चिह्न लगाया जाता है और अनधिकृत पहुंच रोकने के लिए उन्हें विशेष गुलाबी कागजी सील से बंद किया जाता है। एक ईवीएम सेट में कम से कम एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन होती है।

बेहतर तालमेल का परिणाम, लश्कर का आखिरी स्थानीय आतंकी ढेर

अमित शाह ने जवानों को दी बधाई

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों ने लतीफ भट को मार गिराया। वहीं, उसका एक आतंकी सहयोगी उमर निसार भी इससे एक दिन पहले कुलगाम में मारा गया था।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस पूरे अभियान को जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी), भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से अंजाम दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहद उच्च स्तर का तालमेल देखने को मिला। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के बहादुर जवानों को सलाम करते हुए कहा कि देश उनके साहस को नमन करता है।

आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा, हमारे जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी लतीफ भट को मार गिराकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिस पर लाखों रुपये का इनाम था। सुरक्षा बलों ने उसे सरेंडर करने का पूरा मौका दिया, यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी बुलाया, लेकिन वह एक मस्जिद के अंदर छिप गया। हमारी सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों



ने मस्जिद का पूरा सम्मान बनाए रखा; इसकी दीवारों पर एक भी गोली नहीं लगी और उसे तभी मार गिराया गया जब उसने भागने की कोशिश की।

बता दें के सुबह आतंकी लतीफ भट को सुरक्षाबलों ने बार-बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकी को वीडियो कॉल भी किया था। अफसरों ने आतंकी लतीफ से सरेंडर करने के लिए कहा था। सामने आए वीडियो में एक अधिकारी को भट से यह कहते हुए सुना गया, %हम तुम्हारे साथ हैं।% हालांकि, उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद सुरक्षबलों की कार्रवाई में आतंकी मारा गया। इस ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि भट का साथी, उमर निसार डार, इससे पहले सोमवार को कुलगाम में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था। निसार और लतीफ 11 नवंबर को सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की एक चौकी पर हुए हमले में शामिल थे।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से

वेलिंगटन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार, 19 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए भारतीय तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। वनडे सीरीज 3-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें टेस्ट में भी जीत के साथ दौरे का शानदार अंत करने पर होंगी।



भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलना आसान नहीं होगा। बेसिन रिजर्व की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। खासकर शुरुआती दो दिनों में गेंद को स्विंग और सीम मिलने की संभावना है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को मेजबान टीम के तेज गेंदबाजों के सामने संभलकर खेलना होगा। वनडे सीरीज में आराम दिए जाने के बाद जसप्रीत बुमराह टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार तेज गेंदबाजी के बाकी विकल्पों में शामिल हैं। वहीं अंशुल कंबोज और नीतीश कुमार रेड्डी भी अतिरिक्त गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं।

न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर मिशेल सैंटनर हाथ में फ्रैक्चर के कारण दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टीम में शामिल किया गया है। मेजबान टीम को कप्तान टॉम लैथम, अनुभवी बल्लेबाजों और घरेलू परिस्थितियों से परिचित तेज गेंदबाजों से काफी उम्मीदें होंगी। भारत के लिए यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। शुभमन गिल का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट जीतने से भारत की फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

2 दिन से जारी तेजी पर ब्रेक सेंसेक्स 500 अंक नीचे बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में 2 सेशन से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 500 अंकों की गिरावट के साथ 82031 पर बंद हुआ, जो सेशन के दौरान 81780 तक फिसला। निफ्टी भी 159 अंक टूटकर 25227 पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में भी बिकवाली दर्ज की गई। मिडकैप इंडेक्स सवा फीसदी टूट गया। स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.35 फीसदी की कमजोरी रही। सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो ऑटो, आईटी और मेटल इंडेक्स एनएसई पर 1-2.5 फीसदी तक टूटे। वहीं, मीडिया, फार्मा और सरकारी बैंक शेयरों में तेजी देखने को मिली। पीएल कैपिटल में एडवाइजरी एंड डीलिंग के चीफ विक्रम कसाट के मुताबिक, आज शेयर बाजार में आई गिरावट की वजह निवेशकों की मुनाफावसूली है। नवंबर में बाजार में आई तेज तेजी के बाद निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं।

दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना भारत

नई दिल्ली। भारत 2026-30 की अवधि के लिए दुनिया की सबसे अधिक लचीली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस मामले में भारत ने चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को इन्फोइनडेटा की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, व्यापक आर्थिक लचीलेपन (मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस) की रैंकिंग में भारत 100 में से 71 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहा। ये आंकड़े एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के हवाले से साझा किए गए हैं। इस रैंकिंग में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, जापान और रूस 60-60 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जर्मनी को 59, इटली और ब्राजील को 53-53, ब्रिटेन को 52, फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक मिले।

इस्पात उद्योग आयात पर निर्भर बना रहेगा : टीवी नरेंद्रन

नई दिल्ली। टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने बुधवार को कहा कि भारत में कोकिंग कोयले का भंडार सीमित होने के कारण घरेलू इस्पात उद्योग को अपनी कच्चे माल की जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। घरेलू इस्पात क्षेत्र कोकिंग कोयले के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत अपनी कोकिंग कोयले की करीब 90 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी करता है। आईएसए कमिंग कोल समिट से इतर उन्होंने कहा, भारत में कोकिंग कोयले की उपलब्धता हमारे पास मौजूद भंडार से सीमित है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत में उपलब्ध कोकिंग कोयला घरेलू इस्पात उद्योग की जरूरतों को मात्रा और गुणवत्ता, दोनों के लिहाज से पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में हम आयात पर निर्भर रहेंगे।

स्मार्टफोन बाजार में वीवो को पछाड़ सैमसंग बना नंबर-1

नई दिल्ली। भारत के स्मार्टफोन बाजार में सितंबर तिमाही के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश में स्मार्टफोन शिपमेंट सालाना आधार पर 23.3% घटकर 3.68 करोड़ यूनिट रह गया। आईडीसी ने इसे पिछले एक दशक का सबसे कमजोर फेस्टिव क्वार्टर बताया है। इस गिरावट के बीच सैमसंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वीवो को पछाड़कर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में फिर से नंबर-1 की जगह हासिल कर ली है। वहीं, ऐपल और वीवो के शिपमेंट में भारी गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तिमाही में ऐपल ने भारतीय रिटेलर्स को करीब 37 लाख आईफोन भेजे, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 50 लाख था।

महंगे स्टील की नींव पर कैसे खड़ा होगा 'विकसित भारत'

डॉ. अमृत सागर मित्तल

अगर स्टील खपाने वाले उद्योग कीमतों की मार से कारोबार से ही बाहर हो गए तो क्या भारत विकसित भारत बन सकता है? आज चीनी स्टील भारत के स्टील से करीब 43 प्रतिशत सस्ता है, ऐसे में इंजीनियरिंग गुड्स कारोबारी व अन्य संबंधित उद्योग चीन की कंपनियों के मुकाबले कैसे टिकेंगे? 12 नवम्बर को शंघाई मैटल्स मार्केट और सनसर्स चाइना के घरेलू हाजिर भाव के मुताबिक भारत का हॉट-रोल्ड कॉयल (एच.आर.सी.) 64,000 रुपए प्रति टन था, जबकि चीन के एक्सपोर्ट सौदे 37,000 रुपए प्रति टन थे, वहीं भारतीय कोल्ड-रोल्ड कॉयल (सी.आर.सी.) 75,000 रुपए टन था, जबकि चीनी सी.आर.सी. 43,000 रुपए टन। बिगमिंट के पैमाने भी यही कहानी बयां करते हैं। मुंबई में एच.आर.सी. 63,900 और सी.आर.सी. 75,200 रुपए प्रति टन 4 साल के ऊंचे स्तर पर है और मुट्ठी भर बड़े स्टील उत्पादक 30 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।

ये आंकड़े सिर्फ स्टील उद्योग के नहीं, बल्कि देश की हर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ऑटो-पार्ट्स, बिल्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पर के सामने गंभीर चुनौती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में एम.एस.एम.ई. और व्यापक रोजगार के बिना 2047 के विकसित भारत की उम्मीद बेमानी है। केंद्रीय स्टील मंत्रालय की हाल ही में जारी 'राष्ट्रीय स्टील नीति = विजन 2047' के मसौदे को मुट्ठी भर बड़े उत्पादकों की हिफाजत से आगे बढ़कर पूरे स्टील ईकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धा मजबूत करनी होगी। स्टील भारत की हर इमारत का पहला कच्चा माल है। पुल, बांध, मैट्रो, मकान, खेती मशीनरी, भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सामान और जुड़े उद्योग इसके बड़े खपतकार हैं और भारत में रोजगार के अवसर भी इन्हीं के कंधों पर हैं।



अगर स्टील कीमतों के चलते ये मुकाबले से बाहर हो गए तो जिस विकसित भारत को इन्हें गढ़ना था, सब एक सपना ही रह जाएगा।

स्टील की ऊंची कीमतों के संकट के बीच एम.एस.एम.ई. मायूस हैं, वहीं स्टील के दिग्गज उत्पादक कार्टेल मोनोपली का मजा ले रहे हैं, इसकी गवाह इनकी बैलेंस शीट हैं। टाटा स्टील का अप्रैल से सितम्बर छमाही में 20,035 करोड़ रुपए मुनाफा बीते साल समान अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक रहा। जे.एस.डब्ल्यू. स्टील ने 19,300 करोड़ रुपए लाभ के साथ 36 प्रतिशत बढ़ौतरी दर्ज की। जिंदल स्टील का 5,171 करोड़ रुपए मुनाफा 6 प्रतिशत उछला। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (सेल) के 8,917 करोड़ रुपए मुनाफे में 55 प्रतिशत की बढ़ौतरी मिली, तो इन चारों दिग्गज स्टील निर्माताओं ने इस वित्त वर्ष अप्रैल से सितम्बर के बीच 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो बीते साल की पहली छमाही से 29 प्रतिशत अधिक है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। चीन का सरप्लस स्टील एशियाई बाजारों में बिक रहा है। जबकि भारत का सरकारी पेंडुलम चंद बड़ी स्टील कंपनियों की हिफाजत की ओर झुका है। केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2027 तक 11.5 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी, चीन, जापान और रूस से आने वाले एच.आर.सी. की एंटी-डंपिंग जांच और 228 स्टील उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू किया। टैरिफ ड्यूटी स्टील की बढ़ती कीमत के झटके को कुछ समय तक हल्का कर सकती है लेकिन घरेलू बाजार में स्टील के दाम पर लगाम लगाने के लिए दीर्घकालिक नीति की जरूरत है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच देश में स्टील और इससे तैयार उत्पादों का इंपोर्ट 29.5 प्रतिशत बढ़ने का असर साफ दिख रहा है, कि देश में उत्पादित स्टील विदेश से इंपोर्टेड स्टील की तुलना में महंगा है। लुधियाना के साइकिल निर्माता यहां उत्पादन करने की बजाय चीन से साइकिल फ्रेम इंपोर्ट कर रहे हैं। हालात यही रहे तो इंजीनियरिंग गुड्स निर्माता यहां उत्पादन करने की बजाय इंपोर्ट के कारोबार में उतर आएंगे जिससे श्रमिकों के बड़े पैमाने पर बेरोजगार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। 2047 के विकसित भारत में 60 करोड़ टन से ज्यादा स्टील उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। कड़ी परख यह है कि क्या स्टील के हर टन उत्पादन में बढ़ौतरी के पीछे एक्सपोर्ट व अधिक नौकरियां पैदा करने की क्षमता है? बड़े स्टील उत्पादकों की अपनी खदानों के आयरन ओर (लौह अयस्क) की लागत साल-दर-साल सिर्फ 4 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि तैयार स्टील के दाम 24 प्रतिशत तक चढ़े हैं।

प्रदेश में धूमधाम से मना आंवला नवमी का पर्व महिलाओं ने आंवले के पेड़ के नीचे किया भोजन

वृक्ष की पूजा -परिक्रमा कर की संतान सुख और परिवार की खुशहाली की कामना



रायपुर। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आंवला नवमी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना, दान-पुण्य कर सुख-समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति की कामना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी विश्वास के साथ हम महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित कर पूजा करती हैं, वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु तथा घर में सुख-शांति की कामना करती हैं। आंवला नवमी की एक विशेष परंपरा आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने की है। महिलाएं पूजा-अर्चना के बाद वृक्ष की छांव में परिवार और परिजनों के साथ भोजन करती हैं। इस अवसर पर आंवला भात का विशेष महत्व रहता है।

मान्यता है कि इस दिन पूजा और दान-पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक आस्था के साथ सेहत और पर्यावरण का संदेश

श्रद्धालुओं ने बताया कि आंवला नवमी का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। आंवला औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी माना गया है।

यही वजह है कि इस पर्व में धार्मिक आस्था के साथ आरोग्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव भी जुड़ा है। जिस वृक्ष को हमारी परंपरा में पूजनीय स्थान दिया गया है, वह हमें पेड़ों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। आधुनिक जीवनशैली में जब प्रकृति का संतुलन लगातार चुनौती का सामना कर रहा है, तब आंवला नवमी जैसे पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण की अहमियत भी याद दिलाते हैं।

भगवान विष्णु जी की पूजन की परम्परा



ज्योतिष गुरु डॉक्टर पण्डित मनोज शुक्ला के अनुसार, आंवला नवमी को अक्षय तिथि माना गया। इस दिन महिलाओं ने संतान सुख, परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखा। श्रद्धालुओं ने सुबह स्नान और तर्पण के बाद आंवला वृक्ष की पूजा की। नवमी की कथा का श्रवण कर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन किया गया। इसके बाद अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का दान करने की परंपरा निभाई गई।

आंवले के पेड़ की पूजा करने से मन को बहुत शांति मिली



श्रद्धालु महिला मिसेस शर्मा ने बताया कि हम हर साल आंवला नवमी का व्रत रखते हैं। सुबह स्नान करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की, दूध चढ़ाया, सूत बांधा और परिक्रमा की। हमने अपने बच्चों के सुख, परिवार की खुशहाली और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की। आंवले के पेड़ की पूजा करने से मन को बहुत शांति मिली और अक्षय पुण्य मिला। पूजा के बाद दान-पुण्य भी किया।



जैतू साव मठ में मनाया गया आंवला नवमी का पर्व

रायपुर। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मनाए जाने वाले आंवला नवमी का पर्व जैतू साव मठ में बड़े ही श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत पूजा-अर्चना की। पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। आंवाला नवमी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि- आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि की पूजा-अर्चना के पश्चात प्रसाद प्राप्त करने का अत्यंत महत्व है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा-अर्चना सभी अक्षय होता है। हमें अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए सनातन धर्म का परिपालन करना चाहिए वरिष्ठ नागरिक अजय तिवारी ने कहा कि -हम लोग अपने बाल्यावस्था से ही आंवला नवमी का त्यौहार मनाते हुए आ रहे हैं वर्तमान में इसका स्वरूप पहले से परिवर्तित हुआ है किंतु परिपाटी वही है। इस पावन अवसर पर नगर की माताएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। माताओं ने आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा-अर्चना की एवं प्रसाद ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि आंवला नवमी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। कार्यक्रम में रमेश यदु, देवाशीष मुखर्जी, नरेशचंद्र अग्रवाल, संदीप उपाध्याय,सुमित तिवारी, दीपक पाठक, निर्मल दास वैष्णव सहित अनेक प्रतिष्ठित नागरिक श्रद्धालुजन एवं मठ के भक्तगण उपस्थित थे।

युवा शक्ति ही विकसित भारत-2047 के सपने को साकार करेगी: डेका

राज्यपाल ने वंदे मातरम राज्य युवा शिविर के प्रतिभागियों से किया संवाद



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है। देश की लगभग 35 प्रतिशत आबादी युवा है और यही युवा शक्ति भारत को वर्ष 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। युवाओं की शिक्षा, कौशल, मेहनत और नवाचार देश की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे जीवन में जो भी कार्य करें, पूरी लगन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि उससे समाज और राष्ट्र का हित हो।

राज्यपाल ने बुधवार को लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में मेरा युवा भारत रायपुर द्वारा आयोजित 'वंदे मातरम् राज्य युवा शिविर' में विभिन्न राज्यों से आए युवा स्वयंसेवकों से संवाद किया ।17 से 23 नवंबर 2026 तक आयोजित इस सात दिवसीय शिविर में महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के युवा भाग ले रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के शिविर युवाओं को अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और विचारों को जानने-समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे उनमें आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह गीत मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और राष्ट्रीय गौरव की भावना का प्रतीक है।

युवाओं को सफलता के सूत्र बताते हुए राज्यपाल ने धैर्य , दृढ़ता और स्पष्ट उद्देश्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास, कठोर परिश्रम और अनुशासन भी जरूरी है।

समय की पाबंदी सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। युवाओं को टालमटोल की आदत से बचना चाहिए और आज के कार्य को आज ही पूरा करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।

कार्यशालाओं से युवाओं में होता है क्षमता विकास : प्रो. दयाल

कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी एवं फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कार्यशाला आयोजित



रायपुर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग एवं काजल फिल्म्स एंड रेंटल सर्विस के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को प्रदर्शनी एवं फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज दयाल ने कहा कि कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं की क्षमता और कौशल का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ समाचार पत्रों सहित पूरी मीडिया इंडस्ट्री में व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान दौर में अखबारों को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कार्टून की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक कार्टून बहुत कम समय में बड़ी और गहरी बात प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ कार्टूनिस्ट सागर बिसेन ने कहा कि जो विद्यार्थी पूरी इच्छाशक्ति और लगन के साथ किसी करियर को अपनाते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने विद्यार्थियों से कला को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर काजल फिल्म्स एंड रेंटल सर्विस के अनूप चंद्राकर ने कहा कि व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में डॉ. शैलेन्द्र खंडेलवाल, पंकज नयन पांडे, डॉ. नृपेन्द्र शर्मा, डॉ. आशुतोष मंडावी, सभी अतिथि व्याख्याता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

एबीवीपी रायपुर महानगर की सत्र 2026-27 की नवीन कार्यकारिणी घोषित

रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् रायपुर महानगर की सत्र 2026-27 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा बुधवार को स्वदेशी जागरण मंच कार्यालय में एक समारोह में संपन्न हुई। इस अवसर पर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखाड़िया जी विशेष रूप से उपस्थित रहे।एनआईटी रायपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनुज शुक्ल को महानगर अध्यक्ष और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा छात्र-हितों की लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता श्री सुजल गुप्ता — जिन पर छात्र आंदोलनों के दौरान दो मुकदमे भी दर्ज हुए हैं — को महानगर मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। इस सत्र की कार्यकारिणी में कुल 33 ऊर्जावान सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें महानगर सह-मंत्री के रूप में सुनय बंगाले, भागीरथी साहू, दिव्या वर्मा और निखिल नेताम की घोषणा की गई है।





पेंशन योजना में सुधारों की मांग को लेकर पेंशनरों ने देशभर में किया संयुक्त प्रदर्शन

रायपुर। राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में जारी पेंशन योजना में सुधारों की मांग पर आज ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन द्वारा देशभर के बीमा कार्यालयों के समक्ष संयुक्त प्रदर्शन कर सभाएं ली गईं तथा प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया। रायपुर मंडल में उक्त दोनों संगठनों के आह्वान पर आज भोजनावकाश के दौरान सैकड़ों पेंशनर्स एवं सेवारत कर्मचारियों व अधिकारियों ने एलआईसी के पंडरी स्थित मंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सभा ली तथा वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता एआईआईपीए के रायपुर मंडल के अध्यक्ष का. श्रीकांत पेंढारकर ने की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एआईआईपीए के राष्ट्रीय सहसचिव का. अतुल देशमुख ने सार्वजनिक क्षेत्र की एलआईसी एवं जीआईसी के पेंशनर्स हेतु निश्चित समयावधि पर पेंशन का अपग्रेडेशन करने, 1987 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को दी जा रही।

मुख्य सचिव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा



रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर धान खरीदी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने खरीदी केंद्रों पर सुचारू संचालन करने के लिए अधिकारियों से जमीनी स्तर की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता, आवश्यक संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विकासशील ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे धान खरीदी से जुड़े सभी पहलुओं जैसे बारदाने की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, किसानों को समय पर भुगतान और अवैध धान के परिवहन रोकने की कुशल प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

धान खरीदी में अन्नदाताओं को न हो कोई असुविधाः कश्यप



रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस बीच, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है। मंत्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में विशिष्ट पहचान मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था हो। धान के उठाव और भंडारण में कमी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जाएं।

मध्यप्रदेश से अवैध रूप से लाए जा रहे 75 बोरी धान वाहन सहित जप्त

रायपुर। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने मध्यप्रदेश से अवैध रूप से परिवहन कर लाया जा रहा 75 बोरी धान वाहन सहित जब्त किया है। टीम ने धान के परिवहन से संबंधित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर जिले में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं मंडी विभाग की टीम द्वारा अवैध परिवहन और भंडारण पर नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखने तथा नियमित जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर समर्थन मूल्य पर खपाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में धान के अवैध परिवहन, भंडारण एवं खपाने के विरुद्ध जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि धान खरीदी व्यवस्था सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसानों के हित में बनी रहे।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, चोरी का माल खरीदने वाला ज्वेलर भी पकड़ाया

लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण सहित नगदी रकम चोरी करने वाला आरोपी रसोईया गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थी के घर में खाना बनाने वाला रसोईया ही चोर निकला। मौका पाकर समय-समय पर घर की अलमारी से आभूषण व नगदी रकम की चोरी करने वाले आरोपी रसोईया बबलू मिश्रा को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। चोरी के आभूषणों को खरीदने वाले ज्वेलर संतोष सोनी को भी धारा 317(2) बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरात जुमला कीमती लगभग 3,15,000 रुपये जब्त किए गए हैं।

प्रार्थी पदमेश दुबे निवासी भावना नगर, खम्हारडीह, रायपुर ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर की अलमारी



के लॉकर से विगत 2-3 माह से सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के एवं नगदी रकम चोरी हो रही थी। संदेह होने पर घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। 15 नवंबर को परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में घर में काम करने वाला कुक बबलू मिश्रा लॉकर से जेवरात एवं नगदी चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। आरोपी लगभग 15 लाख कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के एवं नगदी चोरी कर ले गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 464/26 धारा 306 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला तथा पुलिस उपायुक्त (उत्तर क्षेत्र) श्रीमती दीपमाला कश्यप द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आरोपी की शीघ्र पहचान कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार करना बताया गया। आरोपी द्वारा चोरी के कुछ आभूषणों को कुशालपुर पुरानी बस्ती निवासी संतोष सोनी को बिक्री करना तथा कुछ को मणप्पुरम गोल्ड लोन में गिरवी रखना बताया गया।

जिस पर संतोष सोनी की पतासाजी कर उसे भी पकड़ा गया। तथा मणप्पुरम गोल्ड लोन में गिरवी रखी गई चोरी के आभूषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

आरोपी बबलू मिश्रा एवं संतोष सोनी को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरात जुमला कीमती लगभग 3,15,000 रुपये जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण में धारा 317(2), 3(5) बीएनएस जोड़ी गई है।

एक शब्द की अभिव्यक्ति के अंदाज़ अलग-अलग, यही रचनात्मकता: गिरीश पंकज

रायपुर। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार, उसकी समृद्ध साहित्यिक एवं रचनात्मक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक एवं प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यालय संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में 'गिरीश पंकज', प्रख्यात वरिष्ठ साहित्यकार, कवि एवं व्यंग्यकार ने सहभागिता की। कार्यशाला का मुख्य विषय एक शब्द अनेक अंदाज—हिंदी में अभिव्यक्ति की रचनात्मकता रहा। अपने व्याख्यान में गिरीश पंकज ने हिंदी भाषा की अभिव्यक्तिगत विविधता, शब्दों की सामर्थ्य तथा भाषा के रचनात्मक प्रयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक एवं सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों, भावों एवं परिस्थितियों में अलग-अलग अर्थों और प्रभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। उन्होंने भाषा को केवल संवाद का माध्यम न मानकर विचारों, भावनाओं एवं सृजनात्मकता की प्रभावशाली अभिव्यक्ति का साधन बताया। उनके व्याख्यान ने हिंदी भाषा की सहजता, रोचकता एवं अभिव्यक्ति की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में सरल, सहज, स्पष्ट एवं प्रभावी हिंदी के प्रयोग पर भी बल दिया तथा दैनिक कार्यप्रणाली में हिंदी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा के रचनात्मक एवं व्यावहारिक प्रयोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं।



आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.